रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1973/श्रावण 13, 1895
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1973/ SRAVANA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1973

का. आ. 2099.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) द्वितीय संशोधन नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 को—

(क) नियम 15 के उपनियम (1) में "कोई अन्य नियोजन ग्रहण नहीं करेगा" शब्दों के स्थान पर "किसी अन्य नियोजन के लिए बातचीत या उसे ग्रहण नहीं करेगा," शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) नियम 18(1) में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई सरकारी सेवक, स्वयं अपने या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में किसी जंगम सम्पत्ति की बाबत कोई संव्यवहार करता है, तो वह, यदि वर्ग 1 या वर्ग 2 पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 1,000.00 रु. या वर्ग 3 या वर्ग 4 पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में 500.00 रु. से अधिक हो उसकी रिपोर्ट ऐसे संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर विहित प्राधिकारी को करेगा ।

परन्तु विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी, यदि ऐसा कोई संव्यवहार :—

(1) ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया हो जिसका उस सरकारी सेवक के साथ शासकीय व्यवहार हो, या

(2) किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यवहारी की मार्फत से अन्यथा किया गया हो।"

[संख्या 25/15/72-स्थापना (ए)]

एस. कृष्णन, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 16th July, 1973

S.O. 2099.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules, further to amend the Central Services (Conduct) Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Conduct) **Second** Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964—

(a) in rule 15, in sub-rule (1), for the words "undertake any other employment", the words "negotiate for or undertake any other employment" shall be substituted;

(b) in rule 18, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Where a Government servant enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of a member of his family, he shall, within one month from the date of such transaction, report the same to the prescribed authority, if the value of such property exceeds Rs. 1,000.00 in the case of a Government servant holding any Class I or Class II post or Rs. 500.00 in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post:

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained if any such transaction is—

(i) with a person having official dealings with the Government servant; or

(ii) otherwise than through a regular or reputed dealer."

[No. 25/15/72-Ests(A)]

S. KRISHNAN, Director

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 1973

का. आ. 2100.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 228-रघुनाथपुर (अ. जा.) सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कालाबरन बाउड़ी, ग्राम नाडीहा, पो. रामपुर, जिला पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कालाबरन बाउड़ी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प ब.-वि स./228/71(74)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 23rd June, 1973

ORDER

S.O. 2100.—WHEREAS the Election Commission is satisfied that Shri Kalabaran Bauri, Village Nadiha, P. O. Rampur, District Purulia (West Bengal) a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 228-Raghunathpur (SC) constituency, held in March, 1971, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

AND WHEREAS, the said candidate even after the due notice has not lodged any account and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 110A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kalabaran Bauri to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/228/71(74)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1973

का. आ. 2101.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि मार्च, 1971 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 27-करनदीघी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शेक हसीबुर, ग्राम डलखोला, पो. डलखोला, जिला पश्चिम दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शेक हसीबुर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. प. ब.-वि. स./27/71(75)]

ए. एन सेन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 1973

S.O. 2101. -Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sk Hasibur, Village Dalkhola, P.O. Dalkhola, district West Dinajpur (West Bengal) a contesting candidate for election to the West Bengal Legislative Assembly from 27-Karandighi constituency, held in March, 1971 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sk. Hasibur to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No WB-LA/27/71(75).]

A. N. SEN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1973

का.आ. 2102.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 16 राजकोट-1 निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मवानी शशीकांत केशवलाल, हाथीखाना शेरी नं. 3, वनद् की बिल्डिंग के समीप, मार्फत कनसारा केशवलाल श्री भुवनदास, राजकोट, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मवानी शशीकांत केशवलाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[गुज.-वि. स./16/72(20).]

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1973

S.O. 2102.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mavani Shashikant Keshavlal, Hathikhana Sheri No. 3, Near Vanad's Building, C/o Kansara Keshavlal Tribhovandas, Rajkot Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 16-Rajkot I constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mavani Shashikant Keshavlal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/16/72-(20)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

का. आ. 2103.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 30 कुटटीयाना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मन्दाविया सुखदेव गोकलदास, निकट सन्यास आश्रम, गिरधर जीवन की बन्दी, स्टेशन रोड़, पोरबन्दर, जिला जूनागढ़, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मन्दाविया सुखदेव गोकलदास को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[गुज.-वि. स./30/72(23).]

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1973

S.O. 2103.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mandavia Sukhdev Gokaldas, Near Shanyash Ashram, Vandi of Girdhar Jivan, Station Road, Porbandar, District Junagadh, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 30-Kutlyana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mandavia Sukhdev Gokaldas to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No GJ-LA/30/72(23)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

का. आ. 2104.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 11-गुहागर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले

उम्मीदवार श्री शान्ताराम सोनू सोलकर, स्थान एवं पोस्ट असगोली, तालुक गुहागर, जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शान्ताराम सोनू सोलकर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[महा.-वि. स./11/72(36).]

ORDER

New Delhi, the 30th June, 1973

S.O. 2104.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shantaram Sonu Solkar. At and Post Asgoli, Taluka Guhagar, District Ratnagiri (Maharashtra), a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Maharashtra Legislative Assembly from 11-Guhagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shantaram Sonu Solkar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. MT-LA/11/72(36).]

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1973

का. आ. 2105.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 101 अवनाशी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री टी. पी. मरूथाचलम थान्नीरपंडाल पालायाम, उपपिलीपालायाम पो. कोयम्बत्तूर जिला, तमिलनाडु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री टी. पी. मरूथाचलम के संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.-वि. स./101/71(64).]

ORDER

New Delhi, the 6th July, 1973

S.O. 2105.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri T. P. Maruthachalam, Thanneerpandalpalayam, Uppilipalayam P.O. Coimbatore Distt. (Tamil Nadu) a contesting candidate for the general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in March, 1971, from 101-Avanashi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri T. P. Maruthachalam to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament of or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN/LA/101/71(64).]

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1973

का. आ. 2106.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6 रापड़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कम्भर नरशी भूरा, नथनी वासा (कुम्भरोनोवास) डा. भाचाउ तालुक भाचाउ, कच्छ गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कुंभर नरशी भूरा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज.-वि. स./6/72(24).]

ORDER

New Delhi, the 9th July, 1973

S.O. 2106.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kunbhar Narshi Bhura, Nathani was (Kunbharono was), P. O. Bhachau, Taluka Bhachau, Kutch, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 6-Rapar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kunbhar Narshi Bhura to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-LA/6/72(23)]

आदेश

का. आ. 2107.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 138-बड़ौदा रूरल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चौहान हिम्मत सिंह प्रभात सिंह सलसत, पो. कलाली, तालुक, बड़ौदा, जिला बड़ौदा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चौहान हिम्मत सिंह प्रभात सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. गुज.-वि. स./138/72(25)]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

S.O. 2107.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chauhan Himatsinh Prabhatsinh, Talsat, Post Kalali, Taluka Baroda, District Baroda, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 138-Baroda Rural constituency, has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chauhan Himatsinh Prabhatsinh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ-LA/138/72(25)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1973

का. आ. 2108.—अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भू-राजस्व व भूमि सुधार विनियम 1966 (1966 का 2) की धारा 6 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री रमेशचन्द्र को 18 दिसम्बर, 1972 के अपराह्न से उक्त विनियम के प्रयोजन हेतु, अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह के जिले के उप-आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि अधिसूचना को 18 दिसम्बर, 1972 के अपराह्न से लागू किया जाय, जिस तारीख को श्री रमेशचन्द्र ने उप-आयुक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह, के पद का कार्यभार संभाला था। इससे किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं. 23/2/73-ए. एन. एल.]

जयाकर जानसन, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th July, 1973

S.O. 2108.—In pursuance of section 6 of the Andaman and Nicobar Islands Land Revenue and Land Reforms Regulation, 1966 (2 of 1966) the Central Government hereby appoints Shri Ramesh Chandra to be the Deputy Commissioner for the District of Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said regulation with effect from the afternoon of the 18th December, 1972.

Explanatory Memorandum

The Government of India have decided that Notification be made effective from the afternoon of the 18th December, 1972, from which date Shri Ramesh Chandra assumed charge of the post of Deputy Commissioner, Andaman and Nicobar Islands. No person is likely to be adversely affected.

[No. 23/2/73-ANL]

JAYAKER JOHNSON, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1973

का. आ. 2109.—विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 1 सितम्बर, 1972 की अधिसूचना सं. का. आ. 569 (ई) के अधीन 'नागा नैशनल कौन्सिल' 'फैडरल गवर्नमैन्ट आफ नागालैन्ड' 'नागा आर्मी' 'किम हाओ' (उच्च सदन) तथा 'तातार हो हो' (प्रतिनिधि सभा) और फैडरल सुप्रीम कोर्ट' को तथा इनके अधीनस्थ अन्य निकायों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त संगठनों के किसी सदस्य द्वारा किये गये उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराधों के बारे में, मणिपुर में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की शक्ति का प्राधिकार, एतद्द्वारा, पर्वतीय आयुक्त (हिल कमिश्नर), मणिपुर को प्रदान करती है।

[सं. 1/26/72-पोल (ई)]

New Delhi, the 19th July, 1973

S.O. 2109.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby authorises the Hill Commissioner, Manipur to exercise in Manipur the power to sanction prosecution in respect of all offences punishable under the said Act, committed by any member of the "Naga National Council", the "Federal Government of Nagaland"

the "Naga Army", "Kimhao" (Upper House) and "Tatar Hoho" (Assembly of Representatives) and "Federal Supreme Court," and other bodies under it all of which have been declared as unlawful associations under sub-section (1) of section 3 of the said Act by the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 569 (E), dated the 1st September, 1972.

[No. 1/26/72-Poll (K)]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 2110.—भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड-3 उपखंड (2) दिनांक 14 अप्रैल 1973 की पृष्ठ संख्या 1516 पर प्रकाशित भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल 1973 की अधिसूचना सं. 1/26/72-पोल (के) (का. आ. संख्या 1052) में प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी रूपांतर की चौथी पंक्ति में आने वाले शब्दों 'एक्सरसाइज' तथा 'दि पावर' के बीच शब्द 'इन नागालैन्ड' अन्तःस्थापित किया जायेगा।

[सं. 1/26/72-पोल (के.)]

के. एस. पुरी, उप सचिव।

CORRIGENDUM

S.O. 2110.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 1/26/72-Poll(K), dated the 4th April, 1973 (S.O. No. 1052) published at page 1516 of the Gazette of India Part II Section 3 sub-section (ii) dated the 14th April, 1973 in the English Version the words 'in Nagaland' shall be inserted between the words 'Exercise' and the 'the power' occurring in line 4 of the published notification.

[No. 1/26/72-Poll.(K)]
K. S. PURI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1973

आय-कर

का. आ. 2111.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री आर. भास्कर राव और ए. सुब्बा राव को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अधीन कर-वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2. अधिसूचना सं. 168 (फा सं. 404/67/72-आई टी सी सी) तारीख 1 सितम्बर, 1972 में श्री के. एस. मूर्ति की और अधिसूचना सं. 49 (फा. सं. 404/55/70-आई टी सी सी), तारीख 23 अप्रैल, 1970 में श्री पी. श्रीराममूर्ति की की गई नियुक्तियों को 18 जून, 1973 से रद्द किया जाता है।

3. यह अधिसूचना 18 जून, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 383 (फा. सं. 404/173/73-आई टी सी सी)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 18th June, 1973

INCOME-TAX

S.O. 2111.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri R. Bhaskara Rao and A. Subba Rao who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointments of Sri K. S. Murthy, made in Notification No. 168 (F. No. 404/67/72-ITCC) dated 1st September, 1972 and that of Sri P. Sreeramamurthy made in Notification No. 49 (F. No, 404/55/70-ITCC) dated 23rd April, 1970 are cancelled with effect from 18th June, 1973.

3. This Notification shall come into force with effect from 18th June, 1973.

[No. 383 (F. No. 404/173/73-ITCC)]

नई दिल्ली, 20 जून, 1973

आय-कर

का. आ. 2112.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड 44 के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री जयपाल सिंह को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर-वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, जो अधिसूचना सं. 21 (फा. सं. 16/9/68-आई. टी. बी.) तारीख 26 मार्च, 1966 को अधिक्रांत करती है, तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं. 387 (फा. सं. 404/167/73-आई. टी. सी. सी.)]

एम. एन. नम्बियार, अवर सचिव

New Delhi, the 20th June, 1973

INCOME-TAX

S.O. 2112.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri Jaipal Singh, who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification which supersedes Notification No. 21 (F. No. 16/9/68-ITB) dated 26th March, 1968 shall come into force with immediate effect.

[No. 387 (F. No. 404/167/73-ITCC)]
M. N. NAMBIAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 1973

आय-कर

का. आ. 2113.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनन्द।

[सं. 392 फा. सं. 203/28/73-आई टी. ए. 2]

New Delhi, the 27th June, 1973

INCOME-TAX

S.O. 2113.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

National Diary Development Board, Anand

[No 392/F. No. 203/28/73-ITA. II]

आय-कर

का. आ. 2114.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, विहित अधिकारी, द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

[सं. 393/फा. सं. 203/8/73-आई. टी.ए.-2]

टी. पी. झुनझुनवाला, उप-सचिव

INCOME-TAX

S.O. 2114.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Council of Scientific and Industrial Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income tax Act, 1961.

INSTITUTION

Gujarat University, Ahmedabad

[No. 393 F. No. 203/8/73-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1973

स्टाम्प

का. आ. 2115.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क को जो केरल वित्तीय निगम द्वारा जारी किए जाने वाले सड़सठ लाख रुपये मूल्य के बंधपत्र पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, माफ करती है।

[सं. 21/72-स्टाम्प/फा. सं. 471/65/72-सी. शु. 7]

जे. रामकृष्णन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1973

STAMPS

S.O. 2115.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds to the value of sixty-seven lakhs of rupees, to be issued by the Kerala Financial Corporation, are chargeable under the said Act

[No 21/72-Stamps/F. No. 471/65/72-Cus. VII]

I. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1972

आय-कर

का० आ० 2116.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर से निर्धारित व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे —

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय-कर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2	3
1	केन्द्रीय रेंज-1, नई दिल्ली	1 केन्द्रीय सर्किल 1, 2, 3, 6, 7 और 9 नई दिल्ली। 2 केन्द्रीय सर्किल 1, 2 और 3 जयपुर।
2	केन्द्रीय रेंज-2, नई दिल्ली	1 केन्द्रीय सर्किल 1, 5, 9, 10, 12, 13 और 14, नई दिल्ली।
3	विशेष रेंज-1, नई दिल्ली	1 कम्पनी सर्किल 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 और 20 नई दिल्ली। 2 विशेष रेंज 10, नई दिल्ली। 3 घ-1 जिला, नई दिल्ली।
4	विशेष रेंज-2, नई दिल्ली	1 कम्पनी सर्किल 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 21 और 22, नई दिल्ली। 2 विशेष सर्किल 1, 1 (अतिरिक्त), 2, 2 (अतिरिक्त), 6, 6 (अतिरिक्त) और 7 नई दिल्ली। 3 घ-2 जिला, नई दिल्ली।
5	'ख' रेंज, नई दिल्ली	1 जिला 1(1), 1(2), 1(2) (अतिरिक्त) और 1(3), नई दिल्ली। 2 जिला 3(19), (20), (21), (22) और (23) नई दिल्ली। 3 जिला 7(1), (2), (3) और (4), नई दिल्ली। 4 जिला 9(1), नई दिल्ली। 5 विशेष सर्किल 8 और 8 (अतिरिक्त) नई दिल्ली। 6 परिदाय सर्किल, नई दिल्ली। 7 जिला 3, वार्ड क, क (अतिरिक्त), क(अतिरिक्त-1), ण और ण(अतिरिक्त) नई दिल्ली। 8 वार्ड 7, वार्ड क, क(1) और ख, नई दिल्ली। 9 जिला ख-1, ख-1(1), ग-1(1) ग-2 और ग-3, नई दिल्ली। 10 जिला-1, वार्ड क और क(1), नई दिल्ली। 11 जिला 9, वार्ड क, नई दिल्ली। 12 वार्ड 5(1), (2) और (3), नई दिल्ली। 13 जिला 5, वार्ड क, क(अतिरिक्त), ख, ख(अतिरिक्त), ग घ, ङ, च और छ, नई दिल्ली।

1	2	3
6.	"घ" रेंज, नई दिल्ली	1 जिला 9(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10 अतिरिक्त) और (11), नई दिल्ली। 2. विशेष सर्किल 3, 4 और 4(अतिरिक्त) 3 जिला 8(5), नई दिल्ली। 4. आयकर अधिकारी (कृषिक धन-कर शाखा में विशेष कर्त्तव्य पर अधिकारी), नई दिल्ली।
7	"ङ" रेंज, नई दिल्ली	1 जिला 8(1), (2), (2) (अतिरिक्त) (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), और (19) (अतिरिक्त), नई दिल्ली। 2 जिला 10(12) और (13), नई दिल्ली। 3 जिला 8, वार्ड क, क (अतिरिक्त), ख, ख(अतिरिक्त), ख(अतिरिक्त-1), ख (अतिरिक्त-2), ग, घ, (1), ङ, और च, नई दिल्ली। 4 क-1, क-2, क-3, क-4 क-4(1) और 1(1) जिले, नई दिल्ली। 5 आयकर-एवं-धन-कर सर्किल-8, नई दिल्ली।
8.	"ज" रेंज, नई दिल्ली	1 जिला 6(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 10(अतिरिक्त), (11), (12), (13), (14) और (15), नई दिल्ली। 2 जिला 3(10), (11), (12) 12(अतिरिक्त), (13) और (13) (अतिरिक्त), नई दिल्ली। 3 जिला 6, वार्ड क, क(अतिरिक्त), क(1), क(2), ख(अतिरिक्त), ग, ग(अतिरिक्त), ग(1), ग(1) (अतिरिक्त), घ और ङ, नई दिल्ली। 4 आय-कर-एवं-धन-कर सर्किल 4 और 11, नई दिल्ली।
9.	"झ" रेंज, नई दिल्ली	1 विशेष सर्किल 5 और 9, नई दिल्ली। 2 जिला 2(1), (2), (2) (अतिरिक्त) (3), (4), (5), (6), (7), (8), (8) (अतिरिक्त), (9), (9) (अतिरिक्त) (10), (11), (11) (अतिरिक्त), (12), (12) (अतिरिक्त), नई दिल्ली।
		3. जिला 2, वार्ड क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, क(1), ग(1), ग(1) (अतिरिक्त) और ग(2), नई दिल्ली।
10	"ट" रेंज, नई दिल्ली	1. जिला 5(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (11) (अतिरिक्त), (12), (12) (अतिरिक्त), (13) और (13) (अतिरिक्त), नई दिल्ली। 2 जिला 3(8), (9), (25), (25) (अतिरिक्त) और 26, नई दिल्ली। 3 ख-15 जिला नई दिल्ली।
11.	"ट" रेंज, नई दिल्ली	1 जिला 3(15), (16), (16) (अतिरिक्त), (17), (17) (अतिरिक्त), (18), (18) (अतिरिक्त), (18) (प्रथम अतिरिक्त), (18) (द्वितीय अतिरिक्त), (24), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34) और (35) नई दिल्ली। 2. जिला 3, वार्ड ज, झ, ञ, ट, ठ, क(1), ग(1), ङ(1) च(1), झ(1) और ट(1), नई दिल्ली। 3. विशेष सहायक सर्किल 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 10, नई दिल्ली। 4 विशेष सर्वेक्षण सर्किल 2, 3, 4 और 9, नई दिल्ली। 5. विदेश अनुभाग, नई दिल्ली। 6. आयकर-एवं-धनकर सर्किल-2, नई दिल्ली। 7. ख-6, ख-7, ख-7 (अतिरिक्त), ख-9 और ख-9 (अतिरिक्त) जिले नई दिल्ली।
12.	"ड" रेंज, नई दिल्ली	1. जिला 3(1), 3(1) (अतिरिक्त), 3(1) प्रथम अतिरिक्त (संग्रहण), 3(1) (द्वितीय अतिरिक्त) (संग्रहण), तृतीय (2) 3(2) (अतिरिक्त), (3), (4), (5), (6), (6) (अतिरिक्त), (7) और (7) (अतिरिक्त), नई दिल्ली। 2. जिला 3, वार्ड ख, ग, घ, ङ, च, छ (अतिरिक्त) ज, ङ, ङ(1) और ङ, नई दिल्ली।

(1)	(2)	(3)
13. "ङ" रेंज, नई दिल्ली ।		1. जिला 4(1), (2), (3), (4) (5) (5) (अतिरिक्त), (6), (6) (अतिरिक्त) (7), (8), (9), (10) और (11) नई दिल्ली ।
		2. जिला 4, वार्ड क, ख, ग, घ, और ग(1) नई दिल्ली ।
		3. जिला 3(14), 3 (14), (अतिरिक्त) और 3 (14) (प्रथम अतिरिक्त), नई दिल्ली ।
		4. जिला 5(14), (15), (15) (अतिरिक्त), (16), (16) (अतिरिक्त), (17), (17) (अतिरिक्त), (18), (19), और (20), नई दिल्ली ।
		5. जिला 5, वार्ड क(1) , ख(1), ग(1), च(1), छ(1) (अतिरिक्त) और छ(3) नई दिल्ली ।
		6. जिला घ–12, नई दिल्ली ।
		7. आय-कर-एवं-धन-कर सर्किल 9 और 10, नई दिल्ली ।
14. "ण" रेंज, नई दिल्ली ।		1. सभी सरकारी संक्लस् सर्किल, नई दिल्ली ।
		2. सभी प्राइवेट सम्क्लस् सर्किल, नई दिल्ली ।
		3. आयकर-एवं-धन-कर सर्किल 7, नई दिल्ली ।
		4. आयकर-एवं सम्पदाशुल्क सर्किल, नई दिल्ली ।
15. सहायक आयुक्त (अपील) "क" रेंज, रोहतक ।		1. क-वार्ड, रोहतक ।
		2. कम्पनी वार्ड, रोहतक ।
		3. आयकर अधिकारी, फरीदाबाद
		4. क-वार्ड, हिसार ।
		5. क-वार्ड, सिरसा ।
16. सहायक आयुक्त (अपील) "ख" रेंज, रोहतक ।		1. आयकर अधिकारी, सोनीपत ।
		2. क-वार्ड, गुड़गांव ।
		3. ख-वार्ड, गुड़गांव ।
		4. आयकर अधिकारी, रिवाड़ी ।
		5. आयकर अधिकारी, नरनौल ।
		6. ख-वार्ड, रोहतक ।
		7. ग-वार्ड, रोहतक ।
		8 घ-वार्ड, रोहतक ।
		9 ख-वार्ड, हिसार ।
		10. ग-वार्ड, हिसार ।
		11. ख-वार्ड, सिरसा ।
17. सहायक आयुक्त (अपील) अम्बाला ।		1. क-वार्ड, अम्बाला ।
		2. ख-वार्ड, अम्बाला ।
		3. क-वार्ड, अम्बाला (अतिरिक्त) ।
		4. क-वार्ड, करनाल ।
		5. ख-वार्ड, करनाल ।
		6. ग-वार्ड, करनाल ।
		7. घ-वार्ड, करनाल ।
		8. क-वार्ड, यमुनानगर ।
		9. ख-वार्ड, यमुनानगर ।
		10. क-वार्ड, शिमला ।
		11. ख-वार्ड, शिमला ।
		12. ग-वार्ड, शिमला ।
		13. क-वार्ड, मण्डी ।
		14. आयकर आयुक्त जीन्द ।
		15. आयकर आयुक्त, ख-वार्ड, मण्डी ।
		16. आयकर अधिकारी, पानीपत ।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अंतरित कर दी जाएंगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 1-9-1972 से प्रभावी होगी ।

[सं० 152/फा० सं० 261/15/72-आई० टी० जे०]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 5th August, 1972

INCOME-TAX

S. O. 2116.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and incomes assessed to Income-tax or super-tax in the Income-tax Circles,

Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof:—

SCHEDULE

S. No.	Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2	3
1.	Central Range I, New Delhi.	1. Central Circles I, II, III, VI, VII and XI, New Delhi. 2. Central Circles I, II and III, Jaipur.
2.	Central Range II, New Delhi.	1 Central Circles IV, V, IX, X, XII, XIII and XIV, New Delhi.
3	Special Range I, New Delhi.	1. Companies Circles II, III, VII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX & XX, New Delhi. 2. Special Circle X, New Delhi. 3. D-I District, New Delhi
4.	Special Range II, New Delhi.	1 Companies Circles I, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XVII, XVIII, XXI and XXII, New Delhi. 2. Special Circles I, I(Addl.), II, II(Addl.), VI, VI(Addl.) and VII, New Delhi. 3. D-II District, New Delhi.
5.	'B' Range, New Delhi .	1. District I(1), I(2), I(2) (Addl.) and I(3) New Delhi. 2. District III(19), (20), (21), (22) and (23) New Delhi. 3. District VII(1), (2), (3) and (4), New Delhi. 4. District IX(1), New Delhi. 5. Special Circles VIII and VIII (Addl.), New Delhi. 6. Refund Circle, New Delhi. 7. District III, Wards A, A (Addl.), A(Addl. I), O & O (Addl.), New Delhi. 8. District VII, Wards A, A (I) and B, New Delhi. 9. District B-I, B-I(1), C-I, C-I(1), C-II and C-III, New Delhi. 10. District I, Wards A and A (I), New Delhi. 11. District IX, Ward A, New Delhi. 12. District V(1), (2) and (3), New Delhi. 13. District V, Wards A, A (Addl.), B, B(Addl.), C, D, E, F and G, New Delhi.
6.	'D' Range, New Delhi. .	1. District X(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10) (Addl.) and (11), New Delhi. 2. Special Circles III, IV and IV (Addl.), New Delhi. 3. District VIII (5), New Delhi. 4. Income-tax Officer, (Officer on Special Duty, Agricultural Wealth-tax Branch) New Delhi.
7.	'E' Range, New Delhi .	1. District VIII(1), (2) (Addl.) (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and (19) (Addl.), New Delhi. 2. District X(12) and (13), New Delhi. 3. District VIII, Wards A, A(Addl.), B, B (Addl.), B(Addl.I), B(Addl.II), C, D, D(I), E and F, New Delhi. 4. A-I, A-II, A-III, A-IV, A-IV(I), and I(I) Districts, New Delhi. 5. Income-tax-cum-wealth-tax Circle-VIII, New Delhi.
8.	'H' Range, New Delhi. .	1. District VI(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10)(Addl.), (11), (12), (13), (14) and (15), New Delhi. 2. District III(10), (11), (12), (12) (Addl.), (13) and (13) (Addl.) New Delhi. 3. District VI, Wards A, A (Addl.), A(I), A(II), B (Addl.), C, C(Addl.), C, (I), C(I) Addl., D and F, New Delhi. 4. Income-tax-cum-wealth-tax Circles IV and XI, New Delhi.
9.	'J' Range, New Delhi. .	1. Special Circles V and IX, New Delhi. 2. District II(1), (2), (2)(Addl.) (3), (4), (5), (6), (7), (8) (8) (Addl.), (9), (9) (Addl.) (10), (11), (11)(Addl.), (12) (12) (Addl.) New Delhi. 3. District II, Wards A, B, C, D, E, F, A(I), C(I), C(I) (Addl.), and C(II), New Delhi.
10.	'K' Range, New Delhi. .	1. District V(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (11) (Addl.), (12) (12)(Addl.), (13) & (13) (Addl.) New Delhi. 2. District III(8), (9), (25), (25)(Addl.) and (26), New Delhi. 3. B-XV District, New Delhi.
11.	'L' Range, New Delhi. .	1. District III (15), (16), (16) (Addl.), (17). (17)(Addl.) (18), (18)(Addl.), (18) (Ist Addl.) (18) (IInd Addl.), (24), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34) and (35), New Delhi. 2. District III, Wards H, I, J, K, A(I), C(I), E(I), G(I), I(I) and L, K(I), New Delhi. 3. Special Asstt. Circles I, II, III, VI, VII, VIII and X, New Delhi. 4. Special Survey Circles II, III, IV & IX, New Delhi. 5. Foreign Section, New Delhi. 6. Income-tax-cum-wealth-tax Circle-II, New Delhi. 7. B-VI, B-VII, VB-II(Addl.), B-IX and B-IX (Addl.) Districts, New Delhi.

1	2	3
12.	'M' Range, New Delhi.	1. District III (1), III (1) (Addl.), III(1) Ist Addl. Collections, III(1) (2nd (Addl.) (Collection), III(2), III (2) (Addl.), (3), (4), (5), (6), (Addl.), (7) and (7) (Addl.) New Delhi. 2. District III, Wards B. C, D, F, F, F(Addl.), G, M, M(I) and N, New Delhi.
13.	'N' Range, New Delhi. .	1. District IV (1), (2), (3), (4), (5), (5),(Addl.), (6), (6)(Addl.), (7), (8), (9), (10) and (11), New Delhi. 2. District IV, Wards A, B, C, D and C(I), New Delhi. 3. District III-(14), III (14). (Addl.) and III (14) (Ist Addl.), New Delhi. 4 District V (14), (15), (15) (Addl.), (16), (16) (Addl) (17), (17) (Addl.), (18), (19), and (20), New Delhi. 5. District V, Wards A(I), B(I), C(I), F(I), F(I) (Addl.) and F(III), New Delhi. 6. District D-XII, New Delhi. 7. Income-tax-cum-wealth-tax Circles IX and X, New Delhi.
14.	'O' Range, New Delhi. .	1. All Government Salary Circles, New Delhi. 2. All Private Salary Circles, New Delhi. 3. Income-tax-cum-wealth-tax Circle VII, New Delhi. 4. Income-tax-cum-Estate Duty Circle, New Delhi.
15.	A.A.C. 'A' Range Rohtak.	1. A-Ward, Rohtak. 2. Company Ward, Rohtak. 3. I.T.O. Faridabad 4. A-Ward, Hissar. 5. A-Ward, Sirsa.
16.	A.A.C. 'B' Range, Rohtak.	1. I.T.O. Sonepat. 2 A-Ward Gurgaon. 3. B-Ward, Gurgaon. 4. I.T.O. Rewari. 5. I.T.O. Narnaul. 6. B-Ward, Rohtak. 7. C-Ward, Rohtak. 8. D-Ward, Rohtak. 9. B-Ward, Hissar. 10. C-Ward, Hissar. 11. B-Ward, Sirsa.
17.	A.A.C. Ambala. . .	1. A-Ward, Ambala. 2. B-Ward, Ambala. 3. A-Ward, Ambala (Addl.) 4. A-Ward, Karnal. 5. B-Ward, Karnal. 6. C-Ward, Karnal. 7 D-Ward, Karnal. 8 A-Ward, Yumna Nagar. 9 B-Waid, Yumna Nagar. 10. A-Ward, Simla. 11. B-Ward, Simla. 12. C-Ward, Simla. 13. A-Ward, Mandi. 14. I.T.O., Jind. 15. I.T.O. B-Ward, Mandi. 16. I.T.O. Panipat.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1.9.72.

[No. 152 (F. No. 261/15/72 I.T.J.]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

आय-कर

का० आ०–2117 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना स० 123 (फा० स० 261/9/72 आई० टी० जे०) तारीख 26 जून, 1972 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे —

अनुसूची

क्रम स०	रेंज	आयकर वार्ड सर्किल या जिला
(1)	(2)	(3)
1	विशेष रेंज-I मुम्बई	केवल आयकर, अधिकारी के प्रभारीधीन कम्पनी सर्किल 1(1), 1(2), और 1(3)।
2.	विशेष रेंज–II मुम्बई	1. 1(1), 1(2), 1(3), 1(4) और 1(9) को छोड़कर कम्पनी सर्किल-1। 2. बी०आर०सी० का प्रथम आयकर अधिकारी।
3.	विशेष रेंज–III, मुम्बई	1 केवल आयकर, अधिकारी के प्रभाराधीन कम्पनी सर्किल 1(4) और 1(9)। 2 क-iv वार्ड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और आठवां आयकर अधिकारी। 3 फिल्म सर्किल के आयकर अधिकारी।
18	घ–रेंज, मुम्बई	1 केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवां, छटा, सोलहवां और सत्रहवें आयकर अधिकारी के प्रभार को छोड़कर ख-III वार्ड।

1	2	3
		2. प्रथम, द्वितीय, नवें, चौदहवें और पन्द्रहवें आयकर अधिकारियों के प्रभार को छोड़कर ग- V वार्ड।
22.	च–रेंज, मुम्बई	1. आयकर अधिकारी के प्रभाराधीन 1, 2, 3, 17, 18, 19 और 20 को छोड़कर च-I वार्ड।
		2. आयकर अधिकारी के प्रभाराधीन 1, 2, 3 को छोड़कर च-II वार्ड।
		3. आयकर अधिकारी के प्रभाराधीन 1, 2, 3, 4, 5 और 10 को छोड़कर ग-IV वार्ड।

जहा इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 251 (फा० सं० 261/9/72-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 29th December, 1972

INCOME-TAX

S. O. 2117: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Board's Notification No. 123 (F.No. 261/9/72-ITJ) dated 26th June, 1972 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts, specified in the corresponding entry in column 3 thereof:

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Ward/Circle and District
1	2	3
1.	Special Range I, Bombay	Companies Circle I(1), I(2) and I(3) Income-tax Officers Charges only.
2.	Special Range-II, Bombay.	1. Companies Circle I except I(1), I(2) I(3), I(4) and I(9).
		2. 1st. I.T.O. of B.R.C.
3.	Special Range-III, Bombay.	1. Companies Circle 1(4) and I(9) I.T.Os. Charges only.
		2. 1st, 2nd 3rd and 8th I.T.Os. of A-IV Ward.
		3. I.T.Os. of film Circle.
18.	D-Range, Bombay .	1. B-III Ward except 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 16th and 17th I.T.Os. Charges only.
		2. C-V Ward except 1st, 2nd, 9th, 14th and 15th I.T.Os. Charges.
22.	F-Range, Bombay. .	1. D-I Ward except 1st, 2nd, 3rd, 17th, 18th, 19th and 20th I.T.Os Charges.
		2. D-II Ward except 1st, 2nd and 3rd I.T.Os Charges.
		3. C-IV Ward except 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 10th I.T.Os. Charges.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioners of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof is transferred shall from the date this Notification shall take effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1st, January, 1973.

[No. 251 (F. No.261/9/72-9.T. I. 5]

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1973

आय-कर

का० आ० 2118-आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की अधिसूचना सं० 151 (फा० सं० 261 12/72-आई० टी० ज०) तारीख 5-8-1972 का भागतः उपान्तरण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे:—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर सर्किल, वार्ड और जिले
(1)	(2)	(3)
9.	रेंज-1, मेरठ	(1) क वार्ड, मेरठ
		(2) ख वार्ड, मेरठ
		(3) ग वार्ड, मेरठ
		(4) परियोजना सर्किल, मेरठ
		(5) विशेष सर्किल, मेरठ
		(6) विशेष सर्वेक्षण सर्किल, मेरठ
		(7) क-वार्ड, गाजियाबाद।

1	2	3
10.	रेंज-II, मेरठ	(1) क-वार्ड, ख-वार्ड, ग-वार्ड, मेरठ को छोड़कर मेरठ सर्किल। (2) वेतन सर्किल, मेरठ। (3) हापुड़ (4) क-वार्ड, गाजियाबाद को छोड़कर गाजियाबाद सर्किल।

यह अधिसूचना 25 जनवरी, 1973 से प्रभावी होगी।

[सं० 268 (261/1/73-आई०टी०जे०)]

New Delhi, the 18th January, 1973

Income-tax

S. O. 2118. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf and in partial modification of Boards' Notification No. 151 (F.No. 261/12/72-ITJ) dated 5-8-1972, the Central Board of Direct Taxes here by directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tsax or Super Tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof: –

SCHEDULE

Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards and Districts.
1	2	3
9.	Range-I, Meerut	(i) A-Ward, Meerut. (ii) B-Ward, Meerut. (iii) C-Ward, Meerut. (iv) Project Circle, Meerut. (v) Special Circle, Meerut. (vi) Special Survey Circle, Meerut. (vii) A-Ward, Ghaziabad.
10.	Range-II, Meerut.	(i) Meerut Circle excluding:— A-Ward, B-Ward and C-Ward, Meerut. (ii) Salary Circle, Meerut. (iii) Hapur (iv) Ghaziabad Circle excluding A-Ward, Ghaziabad.

This Notification shall take effect from 25th January, 1973.

[No. 268 (261/1/73-ITJ)]

आय-कर

का. आ. 2119.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं. 100 (फा. सं. 261/7/72-आई. टी. जे.) तारीख 31 मई, 1972 को उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

2. उक्त अनुसूची में भोपाल रेंज, भोपाल के सामने स्तम्भ 2 के नीचे क्रम सं. 10 के सामने विद्यमान प्रविष्टि, अर्थात् आय-कर अधिकारी बैतूल, लुप्त कर दी जाएगी।

3. उक्त अनुसूची में ग्वालियर रेंज, ग्वालियर के सामने स्तम्भ 2 के अधीन निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

सं. 10 : आयकर अधिकारी, बैतूल

यह अधिसूचना 31-1-73 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

यह संशोधन, प्रत्येक सहायक आयुक्त (अपील) के पास पर्याप्त कार्यभार के प्रयोजन के लिए कार्य के पुनः आबंटन के कारण आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त टिप्पण इस अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकारक रूप में आशयित है।

[सं. 269 (फा. सं. 261/2/73 आई. टी. जे.)]

पी. के. शरण, अवर सचिव

Income-tax

S.O. 2119.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of Income tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct taxes, hereby makes the following amendments in the schedule appended to its Notification No. 100 (F. No. 261/7/72-ITJ) dated 31st May, 1972 as amended from time to time viz :—

2. In the said schedule against Bhopal Range, Bhopal under column 2 the existing entry against Sl. No. 10 namely, Income-tax Officer, Betul, shall be ommitted.

3. In the said schedule against Gwalior Range, Gwalior under column 2, the following shall be added namely :—

No. 10 : Incometax Officer, Betul.

4. This notification shall take effect from 31-1-73.

Explanatory Note :

The amendment has become necessary on account of re-allocation of work for purposes of adequate work load with each Appellate Asstt. Commissioners.

(The above note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 269 (F. No. 261/2/73-ITJ)]
P. K. SHARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर 1972

आय-कर

का० आ० 2120.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 मई, 1963 के पृष्ठ 1454–1457 पर का० आ० 1293 के रूप में प्रकाशित अपनी समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 20 (फा० सं० 55/1/62-आई टी), तारीख 30 अप्रैल, 1963, से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है —

1 क्रम सं० 15क के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
15-क कानपुर-I	कानपुर	1. सर्किल 1, कानपुर। 2 सर्किल 2 कानपुर के बोर्ड ii (1) और ii (6) । 3. वेतन सर्किल, कानपुर। 4. कंपनी सर्किल, कानपुर। 5. विशेष सर्किल, कानपुर। 6. बांदा सर्किल। 7 उन्नाव सर्किल। 8. झांसी सर्किल। 9 फतेहपुर सर्किल। 10. मैनपुरी सर्किल। 11. अलीगढ़ सर्किल। 12. हाथरस सर्किल। 13. मेरठ सर्किल। 14. हापुड़ सर्किल। 15. वेतन सर्किल, मेरठ। 16. गाजियाबाद सर्किल। 17. संपदा शुल्क एवं आयकर सर्किल, कानपुर। 18. संपदा शुल्क एवं आयकर सर्किल, देहरादून।

2 विद्यमान क्रम सं० 15क के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

1	2	3
15-ख कानपुर ii	कानपुर	1. सर्किल ii कानपुर वार्ड ii (1) और ii (6) को अपवर्जित करते हुए। 2. फतेहगढ़ सर्किल। 3. इटावा सर्किल। 4. फिरोजाबाद सर्किल। 5. सर्किल i आगरा। 6. सर्किल ii आगरा। 7. एटा सर्किल। 8. मथुरा सर्किल। 9. मुजफ्फरनगर सर्किल। 10. रुड़की सर्किल। 11. सहारनपुर सर्किल। 12. देहरादून सर्किल।

यह अधिसूचना 15-11-72 से प्रभावी होगी।

[सं० 219/फा० सं० 185/25/72-आई टी (ए आई)]

New Delhi, the 14th November, 1972

INCOME-TAX

S.O.2120—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its notification No. 20 (F. No. 55/1/62-IT) dated the 30th April, 1963 published as S.O. 1293 on pages (1454-1457 of the Gazette of India, part II Section 3 sub-section (ii) dated the 11th May, 1963 as amended from time to time.

1. Existing entries under column (1), (2) and (3) against S. No. 15A shall be substituted by the following entries :—

Commissioners of Income-tax	Head-Quarters	Jurisdiction
1	2	3
15A Kanpur I	Kanpur	1. Circle I, Kanpur 2. Wards II(1) and II(6) of Circle II, Kanpur. 3. Salary Circle, Kanpur. 4. Companies Circle, Kanpur. 5. Special Circle, Kanpur. 6. Banda Circle. 7. Unnao Circle. 8. Jhansi Circle. 9. Fatehpur Circle. 10. Mainpuri Circle. 11. Aligarh Circle. 12. Hathras Circle. 13. Meerut Circle. 14. Hapur Circle. 15. Salary Circle, Meerut. 16. Ghaziabad Circle. 17. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Kanpur. 18. Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Dehra Dun.

2. After the existing S. No. 15A, the following shall be added :—

1	2	3
15B Kanpur II	Kanpur	1. Circle II, Kanpur excluding Wards II(1) and II(6) 2. Fatehgarh Circle. 3. Etawah Circle. 4. Firozabad Circle. 5. Circle I, Agra. 6. Circle II, Agra. 7. Etah Circle. 8. Mathura Circle. 9. Muzaffarnagar Circle. 10. Roorkee Circle. 11. Saharanpur Circle. 12. Dehra Dun Circle.

This notification shall take effect from 15-11-72.

[No. 219 /F. No. 185/25/72-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 2121.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 मई, 1963 के पृष्ठ 1454-1457 पर का० आ०

1293 के रूप में प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 20 (फा० सं० 55/1/62-आई टी), तारीख 30-4-1963, में उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. क्रम सं० 10 के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
10 बंगलौर-1	बंगलौर	1 सर्किल-2, बंगलौर।
		2. कम्पनी सर्किल, बंगलौर।
		3. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, बंगलौर।
		4. तुमकुर सर्किल, तुमकुर।
		5 चन्नापटना सर्किल, चन्नापटना।
		6. वेतन सर्किल, बंगलौर।
		7. मैसूर सर्किल, मैसूर।
		8. मंगलौर सर्किल, मंगलौर।
		9. उडिपी सर्किल, उडिपी।
		10 कुर्ग सर्किल, मर्केरा।
		11 मण्डया सर्किल, मण्डया।
		12. बेलगांव सर्किल, बेलगांव।
		13. पणजी सर्किल, पणजी।
		14. मारगाओ सर्किल, मारगाओं।
		15. बीजापुर सर्किल, बीजापुर।
		16. बगलकोट सर्किल, बगलकोट।
		17. कारवार सर्किल, कारवार।
		18. संपदा शुल्क एवं आय-कर सर्किल, बंगलौर।
		19. संपदा शुल्क एवं आय-कर सर्किल, मंगलौर।
		20. संपदा शुल्क एवं आय-कर सर्किल, हुबली।

2. विद्यमान क्रम सं० 10 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

1	2	3
10-क	बंगलौर	1. सर्किल 1 बंगलौर।
		2 कोलार सर्किल कोलार।
		3 हुबली सर्किल, हुबली।
		4 धारवाड़ सर्किल, धारवाड़।
		5. गडग सर्किल, गडग।
		6 रायचूर सर्किल, रायचूर।
		7. गुलबर्गा सर्किल, गुलबर्गा।
		8. शिमोगा सर्किल, शिमोगा।
		9. चित्रदुर्ग सर्किल, चित्रदुर्ग।
		10. हासपेट सर्किल, हासपेट।
		11 बेलारी सर्किल, बेलारी।
		12 चिकमगालूर सर्किल, चिकमगालूर।
		13. हसन सर्किल, हसन।
		14. दवनगीर सर्किल दवनगीर।

यह अधिसूचना 15-11-1972 से प्रभावी होगी।

[सं० 220/फा० सं० 187/25/72-आई०टी० (ए०आई०)]

INCOME-TAX

S.O.2121.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to its Notification No. 20 (F.No. 55/1/62-IT) dated the 30-4-1963 published as S.O. 1293 on pages 1454-1457 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 11th May, 1963 as amended from time to time.

I. Existing entries under Columns (1), (2) and (3) against S.No. 10 shall be substituted by the following entries:—

Income-tax Commissioners	Head-quarters	Jurisdiction
10. Bangalore-I	Bangalore.	1. Circle-II, Bangalore.
		2. Company Circle, Bangalore
		3. Special Survey Circle, Bangalore.
		4. Tumkur Circle, Tumkur.
		5. Channapatna Circle, Channapatna.
		6. Salary Circle, Bangalore.
		7. Mysore Circle, Mysore.
		8. Mangalore Circle, Mangalore.
		9. Udipi Circle, Udipi.
		10. Coorg Circle, Mercara.
		11. Mandya Circle, Mandya.
		12. Belgaum Circle, Belgaum.
		13. Panaji Circle, Panaji.
		14. Margao Circle, Margao.
		15. Bijapur Circle, Bijapur.
		16. Bagulkot Circle, Bagulkot.
		17. Karwar Circle, Karwar.
		18. Estate Duty Cum Income-tax Circle, Bangalore.
		19. Estate Duty Cum Income-tax Circle, Mangalore.
		20. Estate Duty Cum Income-tax Circle, Hubli.

2. After the existing S.No. 10, the following shall be added:—

1	2	3
10A	Bangalore.	1. Circle-I, Bangalore.
		2. Kolar Circle, Kolar.
		3. Hubli Circle, Hubli.
		4. Dharwar Circle, Dharwar.
		5. Gadag Circle Gadag.
		6. Raichur Circle, Raichur.
		7. Gulbarga Circle, Gulbarga.
		8. Shimoga Circle, Shimoga.
		9. Chitradurga Circle, Chitradurga.
		10. Hospet Circle, Hospet.
		11. Bellary Circle, Bellary.
		12. Chickmagalur Circle, Chickmagalur.
		13. Hassan Circle, Hassan.
		14. Davanagere Circle, Davanagere.

This Notification shall take effect from 15-11-1972.

[No. 220/F.No. 187/25/72-IT (AI)]

आय-कर

का० आ० 2122—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 मई, 1963 के पृष्ठ 1454–1457 में (अंग्रेजी में) पर का०आ० 1293 के रूप में प्रकाशित अपनी समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 20 (फा० सं० 55/1/62-आई टी) तारीख 30–4–1963 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है.

1. क्रम संख्या 4, 5, 5क, 5ख और 5ग के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :–

आय कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
4 मुम्बई सिटी-I	मुम्बई	कम्पनी सर्किल I मुम्बई सर्किल फिल्म सर्किल वेतन ब्रांच I मुम्बई रिफण्ड सर्किल अनिवासी रिफण्ड सर्किल वेतन ब्रांच–II विदेशी अनुभाग सम्पदा शुल्क सर्किल
5 मुम्बई सिटी-II	मुम्बई	ए-II वार्ड कम्पनी सर्किल–IV डी-II वार्ड मार्केट वार्ड
5क मुम्बई सिटी-III	मुम्बई	ए–V वार्ड सी–II वार्ड सी–IV वार्ड निष्क्रांत सर्किल I कम्पनी सर्किल II ई वार्ड एक्स वार्ड
5ख मुम्बई सिटी-IV	मुम्बई	सी-I वार्ड ए-I वार्ड ए-III वार्ड कम्पनी वार्ड III बी० एस० डी० (पूर्वी) हुण्डी सर्किल
5ग मुम्बई सिटी-V	मुम्बई	बी III वार्ड सी-V वार्ड कम्पनी सर्किल V डी-I वार्ड जी वार्ड जी० ए० वार्ड

2 विद्यमान क्रम सं० 5ग के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:–

(1)	(2)	(3)
5घ मुम्बई सिटी-6	मुम्बई	ए IV वार्ड बी I वार्ड निष्क्रांत सर्किल–II बी II वार्ड सी III वार्ड बी०एस० डी० (पश्चिम)

यह अधिसूचना 15–11–1972 से प्रभावी होगी।

[सं० 221/फा० सं० 187/25/72 आई टी (ए आई)]

INCOME-TAX

S. O. 2122.— In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 20 (F.No. 55/1/62-IT) dated 30-4-1963 published as S.O. 1293 on pages 1454–1457 of the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii), dated the 11th May, 1963 as amended from time to time.

1. Existing entries under columns (1), (2) and (3) against Serial Nos. 4, 5, 5A, 5B and 5C shall be substituted by the following entries: -

Commissioners of Income-tax	Head-quarters	Jurisdiction
1	2	3
4. Bombay City-I	Bombay	Companies Circle I Bombay Circle Film Circle Salaries Branch I Bombay Refund Circle Non-residents' Refund Circle Salaries Branch II Foreign Section Eastate Duty Circle
5. Bombay City-II	Bombay	A-II Ward Companies Circle IV D-II Ward Market Ward
5A Bombay City-III	Bombay	A-V Ward C-II Ward C-IV Ward Evacuees Circle I Companies Circle II E-Ward X-Ward
5B Bombay City-IV	Bombay	C-I Ward A-I Ward A-III Ward Companies Circle III B.S.D. (East) Hundi Circle
5C Bombay City-V.	Bombay	B-III Ward C-V Ward Companies Circle V D-I Ward G-Ward GA-Ward

II. After the existing S. No. 5C, the following shall be added :—

5D Bombay City-VI	Bombay	A-IV Ward B-I Ward Evacuees Circle II B-II Ward C-III Ward B.S.D. (West)

This notification shall be effective from 15-11-1972.

[No. 221/F.No. 187/25/72-IT (AI)]

आय-कर

का० आ० 2123.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष करबोर्ड, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 मई, 1963 के पृष्ठ 1454–1457 पर का० आ० 1293 के रूप में प्रकाशित, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 20 (फा० सं० 55/1/62-आई टी) तारीख 30, अप्रैल, 1963 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है

1 क्रम सं० 16, 17, 17क, 17ख और 17ग के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी –

आय कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
"16 पश्चिमी बंगाल I	कलकत्ता	1 कम्पनी जिला I 2. प्रतिवाय सर्किल 3. विदेश अनुभाग 4 जिला III-क 5 केन्द्रीय वेतन सर्किल 6 पश्चिमी दीजापुर मालदा 7. जलपाईगुड़ी 8 सिलिगुड़ी 9 दार्जीलिंग 10 कूचबिहार 11 परियोजना सर्किल 12 उत्तरी बंगाल 13. सम्पदा शुल्क सर्किल
17 पश्चिमी बंगाल–II	कलकत्ता	1. कंपनी जिला III, कलकत्ता 2. जिला III(1), कलकत्ता 3. हुण्डी सर्किल, कलकत्ता 4 सिनेमा सर्किल, कलकत्ता 5. परियोजना सर्किल, कलकत्ता
17 (क) पश्चिमी बंगाल–III	कलकत्ता	1. कम्पनी जिला II, कलकत्ता 2. जिला V (2), कलकत्ता 3 विशेष सर्किल III, कलकत्ता 4. रेलवे और प्रकीर्ण वेतन सर्किल, कलकत्ता 5. जिला V—क, कलकत्ता 6. बर्दवान 7 आसनसोल 8. बीर भूमि 9. बांकुरा 10 पुरुलिया 11 पटसन सर्किल, कलकत्ता 12 जिला VII कलकत्ता
17 (ख) पश्चिमी बंगाल–IV	कलकत्ता	1. कम्पनी जिला, IV, कलकत्ता 2. जिला III(2), कलकत्ता 3. जिला I(2), कलकत्ता 4. जिला IV(2), कलकत्ता 5 मुर्शिदाबाद 6 नादिया।
17 ग पश्चिमी बंगाल V	कलकत्ता V	1. जिला V(1), कलकत्ता 2. जिला II(2), कलकत्ता 3. जिला IV(1), कलकत्ता 4. जिला IV (3), कलकत्ता 5. जिला VI कलकत्ता 6. मिदनापुर।"

2 विद्यमान क्रम सं० 17 ग के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा –

1	2	3
"17घ पश्चिमी बंगाल VI	कलकत्ता	1. 24 परगना 2. विशेष सर्वेक्षण सर्किल VIII, कलकत्ता 3. हुगली 4. हावड़ा 5 विशेष सर्वेक्षण सर्किल IX, कलकत्ता 6. जिला I(1), कलकत्ता 7. जिला II(1), कलकत्ता 8. विशेष सर्वेक्षण सर्किल IV, कलकत्ता 9. जिला III(3), कलकत्ता"

यह अधिसूचना 15–11–72 से प्रभावी होगी।

No. 222 (फा. सं. 187/25/72–आई टी ए आई)

INCOME TAX

S. O. 2123.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (i) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 20(F. No. 55/1/62-IT) dated the 30th April, 1963 published as S.O. 1293 on pages 1454-1457 of the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii), dated the 11th May, 1963 as amended from time to time.

1. Existing entries under columns (1), (2) and (3) against S. Nos. 16, 17, 17A, 17B, & 17C shall be substituted by the following entries:—

Income-tax Commissioners	Head-quarters	Jurisdiction
1	2	3
16. West Bengal-I.	Calcutta	1. Comp. Dist. I. 2. Refund Circle. 3. Foreign Section. 4. District III-A. 5. Central Salaries Circle. 6. West Dijapur-Malda. 7. Jalpaiguri. 8. Siliguri. 9. Darjeeling. 10. Cooch-Behar. 11. Project Circle. 12. North Bengal. 13. Estate Duty Circle.
17. West Bengal-II	Calcutta	1. Comp. Dist. III, Calcutta 2. District III(1), Calcutta. 3. Hundi Circle, Calcutta. 4. Cinema Circle, Calcutta. 5. Project Circle, Calcutta.

1	2	3
17A. West Bengal III	Calcutta	1. Comp. Dist. II, Calcutta. 2. Dist. V(2), Calcutta. 3. Special Circle III, Calcutta. 4. Railway and Miscellaneous Salaries Circle, Calcutta, 5. Dist. V-A, Calcutta. 6. Burdwan. 7. Asansol. 8. Birbhum. 9. Bankura. 10. Purulia. 11. Jute Circle, Calcutta. 12. Dist. VII, Calcutta.
17B West Bengal IV	Calcutta	1. Comp. Dist. IV, Calcutta. 2. Dist. III(2), Calcutta. 3. Dist. I(2), Calcutta. 4. Dist. IV(2), Calcutta. 5. Murshidabad. 6. Nadia.
17 C West Bengal V	Calcutta	1. Dist. V(1), Calcutta. 2. Dist. II(2), Calcutta. 3. Dist. IV(1), Calcutta. 4. Dist IV(3), Calcutta. 5. Dist. VI, Calcutta. 6. Midnapore.

2. After the existing S. No. 17C, the following shall be added.

1	2	3
17D West Bengal IV	Calcutta	1. 24 Parganas. 2. Special Survey Circle VIII, Calcutta. 3. Hooghly. 4. Howrah. 5. Special Survey Circle IX, Calcutta. 6. Dist. I(1), Calcutta. 7. Dist. II(1), Calcutta. 8. Special Survey Circle IV. Calcutta. 9. Dist. III (3), Calcutta.

This notification shall take effect from 15-11-72.

[No. 222/F.No. 187/25/72-IT(AI)]

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1972

आय-कर

का० आ० 2124—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 437 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-आई टी) तारीख 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. उक्त अनुसूची में क्रम संख्या 42 छ (ii) के सामने स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविष्टियां हटा दी गई मानी जाएंगी —

2 उक्त अनुसूची में मद ज(v) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा

1	2	3	4	5	6
(VI) पश्चिमी बंगाल सरकार के सब राजपत्रित कर्मचारी जो अपना वेतन और उपलब्धियां पश्चिमी बंगाल राज्य में 24 परगना, हावड़ा और जलपाईगुड़ी के जिला खजानों और उक्त जिलों के उपखजानों से भिन्न जिला खजानों या उप खजानों से प्राप्त करते	आय-कर अधिकारी, ई-वार्ड, सर्किल कलकत्ता	सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण), जो केन्द्रीय वेतन सर्किल, कलकत्ता की बाबत सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया है	सहायक आय-कर आयुक्त आयुक्त (अपील) जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आय-कर अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति विनिहित की गई है।	आय-कर आयुक्त पश्चिमी बंगाल 1, कलकत्ता

यह अधिसूचना 4-12-1972 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 7/फा० सं० 187/24/72-आई टी (ए आई)]

बी० माधवन, अवर सचिव

Now Delhi, the 25th Nov. 1973

INCOME-TAX

S. O. 2124.—In exercise of the powers conferred by the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule annexed to its Notification No. I (F. No. 55/233 6.-IT) dated 18th May, 1964.

1. In the said Schedule entries against serial No. 42 G(ii) under Column 2 shall be treated as deleted.

2. In the said Schedule after the item H(v) following shall be added :

1	2	3	4	5	6
(VI) All Gazetted and non-gazetted employees of the Govt. of West Bengal who draw their pay and emoluments from the District or Sub-Treasuries in the State of West Bengal other than the District Trea-	Income-tax Officer, E-Ward, Central Salaries Circle, Calcutta.	Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the functions of an Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax in respect of	Appellate Asstt. Commissioner of Income-tax who has been invented with powers to hear appeals against the decision of the Income-tax Officer referred to in	Commissioner of Income Tax, West Bengal Calcutta.	

1	2	3	4	5	6
suries of 24-Parganas, Howrah & Jalpaiguri and the Sub-Treasuries of the said District.		Central Salaries Circle, Calcutta.	Col. 3.		

This Notification shall come into force from the 4-12-1972.

B. MADHAVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973

आय-कर

का. आ. 2125.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि केन्द्रीय सर्किल, नागपुर के कृत्य, आय-कर आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई की अधिकारिता से आय-कर आयुक्त, विदर्भ और मराठवाड़ा, नागपुर की अधिकारिता को अन्तरित कर दिए जाएंगे ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1973 को प्रभावी होगी ।

[सं. 282/फा. स. 187/23/72-आई. टी. (ए. आई.)]

New Delhi, the 31st January, 1973

S.O. 2125.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the functions in respect of the Central Circles at Nagpur shall stand transferred from the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax (Central), Bombay to the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax, Vidarbha and Marathwada, Nagpur.

This notification shall take effect on the 1st day of May, 1973.

[No. 282/F. No. 187/23/72-IT(AI)]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1973

आय-कर

का० आ० 2126.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 मई, 1963 के पृष्ठ 1454-1457 पर का० आ० 1293 के रूप मे प्रकाशित अपनी समय-समय पर यथासशोधित अधिसूचना स० 20 (फा० स० 55/1/62-आई टी) तारीख 30 अप्रैल, 1963 से सलग्न अनुसूची मे निम्नलिखित सशोधन करता है :—

क्रम० स० 6 के सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएगी ।

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
6. (केन्द्रीय) मुम्बई	मुम्बई	1. केन्द्रीय अनुभाग 1 से 23 तक, मुम्बई । 2 केन्द्रीय सर्किल, 1 से 1 तक, नागपुर । 3 केन्द्रीय सर्किल, 1 से 2 तक, अहमदाबाद ।

[स० 319/फा० स० 187/6/73-आई टी (ए आई)]

वी० बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

New Delhi, the 27th March, 1973

INCOME-TAX

S. O. 2126.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the schedule appended to its Notification No. 20 (F. No. 55/1/62-IT) dated the 30th April, 1963, published as S.O. 1293 on pages 1454-1457 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 11th May, 1963 as amended from time to time :

The existing entries under columns (1), (2) and (3) against S. No. 6 shall be substituted by the following entries:—

Income tax Commissioner	Head Quarters	Jurisdiction
6 (Central) Bombay.	Bombay	1. Central Sections I to XXIII, Bombay. 2. Central Circles, I to IV, Nagpur. 3. Central Circles, I to II, Ahmedabad.

[No. 319/F. No. 187/6/73-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कानपुर

कानपुर, 19 मई, 1973

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 2127—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 233 के अधीन निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निदेश दिया जाता है कि समाहर्तालय के "माचिसो" के निर्माता उनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री यथा—स्पिलंट्स और वीनर्स, गन्धक तथा पोटासियम क्लोरेट का, संलग्न प्रपत्र मे पृथक दैनिक लेखा रखेंगे । ऐसे निर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 55 के अधीन प्रपत्र आर० टी० 5 मे उक्त कच्ची सामग्री की त्रैमासिक विवरणी भी अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम 10 दिनों के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (रेंज आफिसर) को भेजेंगे तथा उसकी प्रतिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्धित सहायक समाहर्ता को भी भेजेंगे ।

सलग्न कच्ची सामग्री के दैनिक लेखा का प्रपत्र ।

माचिसों के निर्माण के लिये कच्ची सामग्री का दैनिक लेखा

निर्माणी का नाम तथा पता :—

कच्ची सामग्री का विवरण :—

दिनाक	अथ शेष	बीजक संख्या तथा दिनाक	माल भेजने वाले का नाम	प्राप्त मात्रा	योग
1	2	3	4	5	6

प्रयोग की गई मात्रा,		अन्य प्रकार से व्यय की गई मात्रा		बरबाद हुई या विनष्ट की गई मात्रा
माचिसो के निर्माण मे	अन्य माल के निर्माण मे	व्ययन की प्रकृति	मात्रा	
7	8	9	10	11

शतशेष	निर्मित माचिसो की मात्रा	अन्य निर्मित माल की मात्रा	अभ्युक्तियां	निर्धारिती या, उसके अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर
12	13	14	15	16

माह का .....योग ।

टिप्पणी 1—प्रत्येक कच्ची सामग्री के लिये अलग-अलग रजिस्टर बनाये जाने चाहिये ।

2—यदि कोई कच्ची सामग्री उत्पाद शुल्क लगने योग्य एक से अधिक निर्मित माल (विभिन्न टैरिफ मदों के अन्तर्गत आने वाले) या अन्य माल के लिये प्रयोग की जाती है तो स्तम्भ सं० 5 तथा 6 का उपयुक्त रूप से उप-विभाजन करके ऐसे प्रत्येक माल का विवरण देते हुये उसके लिये प्रयोग की गई कच्ची सामग्री की मात्रा अलग-अलग दिखाई जानी चाहिये ।

[सं० 7/73—सं० V(38) (8)70-प्रावि/73/23244]

ज्योतिर्मय दत्त, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, KANPUR

Kanpur, the 19th May, 1973

CENTRAL EXCISE

S.O. 2127. —In exercise of the powers vested under Rule 233 of the Central Excise Rules, 1944 the undersigned directs that the manufacturers of 'Matches' in this Collectorate, shall hereafter maintain a separate daily account of raw materials, namely, splints and Veeners Sulphur and Potassium Chlorate used in the manufacture of matches, in the Form enclosed. Such manufacturers shall also furnish a Quarterly Return of the said raw materials in Form R.T.5. under Rule 55 of the Central Excise Rules, 1944 within the first 10 days of the following quarter, to the Central Excise Range Officer concerned with copies to the Assistant Collector of Central Excise, concerned.

Encl: Form of day-to-day account of raw material.

DAILY ACCOUNT OF RAW MATERIALS FOR THE MANUFACTURS OF MATCHES

Name and address of the Factory:

Description of Raw Material:

Date	Opening Balance	Invoice No. and date	Name of consigner
1	2	3	4

Quantity received	Total	Quantity used in the manufacture of	
		Matches	Other goods
5	6	7	8

Quantity otherwise disposed of		Quantity Wasted or destroyed	Closing Balance
Nature of the disposal	Quantity		
9	10	11	12

			Signature of the Assessee or his Agent
	u		
13	14	15	16
Total for the month			–

NOTES 1. Separate Registers should be maintained in respect of each raw material.

2. If any raw material is used for more than one excisable goods (falling under different tariff items) or other goods manufactured, quantity used for each of such goods should be shown separately along with description of such goods by suitably sub-dividing column 5 and 6.

[No. 7/73—C. No. V (38)(8) 70-Tech./73/23244]

J. DATTA, Collector

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क समाहर्तालय, कलकत्ता

कलकत्ता, 8 जून, 1973

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

का. आ. 2128.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली '44 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हुआ मैं एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली '44 के नियम 9 के उप-नियम (1ए) के अन्तर्गत 'समाहर्ता' के अधिकारों का अपने सम्बद्ध अधिकार क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ताओं को, अधिकृत करता हूं ।

[सी. एन. ओ. 4(16) 24-सी. ई./डब्लू. बी./72]

एन. एन. रायचौधरी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS CALCUTTA

Calcutta, the 8th June, 1973

CENTRAL EXCISE

S O. 2128.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the C.E. Rules, '44, I hereby authorise the 'Assistant Collectors, Central Excise', to exercise within their respective jurisdiction the powers of the 'Collector' under sub-rule (1A) of Rules 9 and 173G of the C.E. Rules, '44.

[C. No. IV(16)24-CE/WB/72]

N. N. ROYCHOUDHURY, Collector.

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, 27 जून, 1973

आदेश

का. आ. 2129.—सर्वश्री यूनियन कार्बाइड इन्डिया लि. 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को यू. एस. ए. आई. डी. ऋण संख्या : 386-एच-207 के अन्तर्गत सिनेमा आर्क कार्बन के निर्माण के लिए कच्चे माल/फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए 1,94,000 रु. मात्र का एक आयात लाइसेंस संख्या : पी/डी/2185249/एस./ए. एन./40/एच/31-32-बैटरी, दिनांक 13-9-71 स्वीकृत किया गया था । बाद में इस लाइसेंस के मूल्य को घटा कर 1,64,000 रु. मात्र कर दिया गया था । यू. एस. ए. आई. डी. के रुक जाने के कारण वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग ने अपने पत्र संख्या : एक (101) (ए) ई री ए (ए) ए आ ई डी/7/246, दिनांक 1-4-72 द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे 1,57,590 रु. मात्र तक के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा रिहा कर दी थी ।

2. उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति उनके द्वारा खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह प्रतिवेदित किया गया है कि लाइसेंस में 90,578 रु. मात्र बाकी बचे थे जिनका उपयोग नहीं किया गया था । लाइसेंस को कलकत्ता सीमाशुल्क कार्यालय, कलकत्ता में पंजीकृत करवाया गया था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या : पी/डी/2185249/एस/ ए. एन, दिनांक 13-9-1971 की मूल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि कार्य सम्बन्धी प्रति जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं. बैटरी/2(9)/70-71/आर. एम.-2]

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 27th June, 1973

ORDER

S.O. 2129.—M/s. Union Carbide India Limited, 5, Parliament Street, New Delhi, were granted Import Licence No. P/D/2185249/S/AN/40/H/31-32/Battery dated 13th September, 1971 under US AID Loan No. 386-H-207 for import of Raw Materials/Spare Parts for the manufacture of Cinema Arc Carbon valued at Rs. 1,94,000 only. Its value was afterwards reduced to Rs. 1,64,000 only. Against this licence the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs by their letter No. F(101)(A)ECA(A)/AID/7/246 dated 1st April, 1972 released free foreign exchange to the extent of Rs. 1,57,590 only due to the pause in US AID.

2. They have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilized balance Rs. 90,578 only. The licence was registered with Calcutta Customs House, Calcutta.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Import Licence No. P/D/2185249/S/AN/dt. 13th September, 1971 has been lost or misplaced and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued separately.

[No. Battery/2(9)/70-71/R.M. II]

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1973

आदेश

का. आ. 2130.—सर्वश्री बम्बई पेपर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी 109, शेख मेमन स्ट्रीट, बम्बई-2 को एम. जी. टिशू पेपर के विनिर्माण के कच्चे माल/संघटकों के आयात के लिए 55,00 रुपये मात्र मूल्य का एक आयात लाइसेंस संख्या : पी/डी/2187125/सी/एक्स एक्स/41/एच/33-34/पेपर दिनांक 14-1-1972 सामान्य मुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदान किया गया था ।

2. उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति उनसे खो गई है । लाइसेंसधारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस पर 35,350 रुपये मात्र बिना उपयोग किए शेष थे । लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय बम्बई में पंजीकृत कराया गया था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदकों ने एक शपथपत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या : पी/डी/2187125, दिनांक 14-1-1972 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देता है कि इसकी अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या : पेपर/14/4/71-72/आर. एम.-2]

ए. के. सरकार, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते मुख्य नियन्त्रक

New Delhi, the 2nd July, 1973

ORDER

S.O. 2130.—M/s. Bombay Paper Manufacturing Company, 109 Shaikh Memon Street, Bombay-2 were granted Import Licence No. P/D/2187125/C/XX/41/H/33-34/Paper dated 14th January, 1972 under GCA for import of Raw Materials/Components for the manufacture of M. G. Tissue Paper valued at Rs. 55,500 only.

2. They have requested for the issue of duplicate Customs Purposes Copy of the above said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence had an unutilized balance of Rs. 35,350 only. The licence was registered with Bombay Custom House.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Import Licence No. P/D/2187125 dated 14th January, 1972 has been lost and directs that a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy is cancelled.

4. The Duplicate Customs Purposes Copy of the licence is being issued separately.

[No. Paper/14/4/71-72/RM. II]

A. K. SARKAR, Dy. Chief Controller

for Chief Controller

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1973

आदेश

का. आ. 2131.—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) को (1) 50 नग स्क्रीन्स 70"×70", (2) फाल्तू पुर्जों के साथ 50 नग मूवी प्रोजेक्टर्स 16 एम एम के आयात के लिए 16,692 रुपये का एक सीमाशुल्क निकासी परीमट संख्या : जी/जे/2339688/एन/डी वाई/36-एच/31-32/एम एल-1, दिनांक 26-8-70 जिसके मूल्य को बाद में बढ़ाकर 1,62,486 रु. कर दिया था, स्वीकृत किया गया था । उस मंत्रालय ने अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परिमट के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परिमट खो गया/अस्थानस्थ हो गया है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परिमट किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका बिलकुल उपयोग नहीं किया गया था । उपर्युक्त तर्क के समर्थन में उस मंत्रालय ने एक अपेक्षित शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परिमट संख्या : जी/जे/2339688, दिनांक 26-8-1970 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि आवेदक को अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परिमट जारी किया जाना चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी परिमट रद्द किया जाता है ।

[संख्या :7/यू. एस. ए. आई. डी.-17/69-70/एम. एल.-1]

एस. के. उस्मानी, उप-मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 3rd July, 1973

ORDER

S.O. 2131.—Ministry of Health and Family Planning, (Deptt. of F.P.) New Delhi was granted a Customs Clearance Permit No. G/J/2339688/N/DY/36/H/31-32/ML. I dated 26th August, 1970 for Rs. 16,692 and later on enhanced to Rs. 1,62,486 for the import of (1) 50 Nos. Screens 70" x 70", (2) 50 Nos. Movie Projectors 16 mm. with spare parts. That Ministry have applied for a duplicate copy of the Customs Clearance Permit on the ground that the original Customs Clearance Permit has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Clearance Permit

was not registered with any Customs House and not utilised. In support of this contention, that Ministry have filed a plan affidavit. I am satisfied that the original Customs Clearance Permit No. G/J/2339688 dt. 26th August, 1970 has been lost/misplaced and direct that a duplicate Customs Clearance Permit should be issued to the applicant. The original Customs Clearance Permit is cancelled.

[No. 7/USAID-17/69-70/ML. I]
S. K. USMANI, Dy. Chief Controller.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1973

का० आ० 2132.—भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

इस अनुसूची में :

1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों के अन्तर्गत "डाक्टर आफ मेडीसिन (शरीर क्रिया विज्ञान) . . .एम० डी० (शरीर क्रिया विज्ञान) इलाहाबाद" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय : नामत:

"मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	मास्टर आफ सर्जरी (श० र० वि०), इलाहाबाद
डाक्टर आफ मेडीसिन (भेषज गुण विज्ञान)	एम० डी० (फार्म०), इलाहाबाद"

2. मद्रास विश्वविद्यालय से संबन्धित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (तंत्रिका शल्य चिकित्सा) . . .एम० सी० एच० (न्यूरो सर्जरी), मद्रास," प्रविष्ट के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय : नामत:

"डाक्टर आफ मेडीसिन (शरीर क्रिया विज्ञान प्रमुख तथा जीव रसायन गौण)	एम० डी० (श० क्रि० वि०) मुख्य तथा जीव रसायन विज्ञान गौण), मद्रास
मास्टर आफ सर्जरी (जेनिटो यूरीनरी सर्जरी)	एम० सी० एच० (जेनिटो यूरिनरी सर्जरी), मद्रास ।
मास्टर आफ सर्जरी (वक्षशल्य चिकित्सा)	एम० सी० एच० (वक्ष-शल्य चि०), मद्रास ।
डाक्टर आफ मेडीसिन (त्वचा विज्ञान)	एम० डी० (त्वचा विज्ञान), मद्रास" ।

3 राजस्थान विश्वविद्यालय से संबन्धित प्रविष्टि में "डाक्टर आफ मेडीसिन (भेषजगुण विज्ञान) . . .एम० डी० (भे० वि०), राजस्थान" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाएं ; नामत:

"मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)	एम० एस० (श० र० वि०), राजस्थान
क्षयरोग एवं वक्ष रोग में डिप्लोमा	डी० टी० सी० डी०, राजस्थान
डाक्टर आफ मेडीसिन (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम० डी० (शरीर क्रि० वि०), राजस्थान
मास्टर आफ सर्जरी (कर्णनासाकण्ठ विज्ञानी)	एम० एस० (क० ना० क०वि०), राजस्थान"

4. मराठवाडा विश्वविद्यालय से संबन्धित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा) . . .एम० एस० (सामा० सर्जरी), मराठवाडा" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं; नामत:

"डाक्टर आफ मेडीसिन (बाल रोग चिकित्सा)	एम०डी० (बाल रोग चि०) मराठवाडा
शिशु स्वास्थ्य मे डिप्लोमा	डी० सी० एच०, मराठवाडा
डाक्टर आव मेडीसिन (औषध विज्ञान)	एम० डी० (औषध वि०), मराठवाडा
डाक्टर आफ मेडीसिन (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	एम० डी० (प्र० एव स्त्री० वि०), मराठवाडा" ।

5 मदुरई विश्वविद्यालय से संबन्धित प्रविष्टियों मे "मास्टर आफ सर्जरी (नेत्रविज्ञान) . . . .एम० एस० (नेत्रविज्ञान), मदुरई" के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां रख ली जाएं, नामत:—

"नेत्रविज्ञान में डिप्लोमा	डी० ओ०, मदुरई
संज्ञाहरण विज्ञान में डिप्लोमा	डी० ए०, मदुरई
मास्टर आफ सर्जरी (स्नायु सर्जरी)	एम० सी० एच०, (स्नायु सर्जरी), मदुरई
डाक्टर आफ मेडीसिन (रोग विज्ञान)	एम० डी० (रोग वि०), मदुरई" ।

(सं० बी० 11015/9/73 एम०पी०टी०)

कु० सती बालकृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Health Department)

New Delhi, the 21st July, 1973

S. O. 2132.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following amendments in the First Schedule to the said Act, namely:

In the said Schedule—

(i) in the entries relating to the University of Allahabad, after the entry "Doctor of Medicine (Physiology)—M.D. (Phy.), All.", the following entries shall be inserted, namely:—

"Master of Surgery (Anatomy	—M.S. (Ana.), All.
Doctor of Medicine (Pharmacology)	—M.D. (Pharm.), All."

(ii) in the entries relating to the University of Madras, after the entry "Master of Surgery (Neuro-Surgery)..M.Ch. (Neuro-Surgery), Madras", the following entries shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Physiology main and Biochemistry subsidiary)	—M.D. (Phy. main & Bio. Chem subsidiary), Madras"
Master of Surgery (Genito-Urinary-Surgery)	—M.Ch. (Genito-Urinary-Surgery), Madras
Master of Surgery (Thoracic Surgery)	—M.Ch. (Thor. Surg.), Madras
Doctor of Medicine (Dermatology)	—M.D. (Derma.), Madras"

(iii) in the entries relating to the University of Rajasthan, after the entry "Doctor of Medicine (Pharmacology)..M.D., (Pharm.) Rajasthan", the following entries shall be inserted namely :—

"Master of Surgery (Anatomy	—M.S. (Ana.), Rajasthan
Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases	—D.T.C.D., Rajasthan.
Doctor of Medicine (Physiology)	—M.D. (Phy.), Rajasthan
Master of Surgery (Oto-rhino-laryngology)	—M.S. (Oto-rhino-laryngology), Rajasthan"

(iv) in the entries relating to the Marathwada University, after the entry "Master of Surgery (General Surgery)..M.S. (Genl. Surg.), Marathwada", the following entries shall be inserted, namely:—

"Doctor of Medicine (Paediatrics)	—M.D. (Paed.), Marathwada
Diploma in Child Health	D.C.H., Marathwada

Doctor of Medicine (Pharmacology)	—M.D. (Pharm.), Marathwada
Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology)	—M.D. (Obst. & Gyn.), Marathwada"

(v) in the entries relating to the Madurai University, after the entry "Master of Surgery (Ophthalmology)..M.S. (Ophth.) Madurai" the following entries shall be inserted, namely:—

"Diploma in Ophthalmology	—D.O., Madurai
Diploma in Anaesthesiology	—D.A., Madurai
Master of Surgery (Neuro-Surgery)	—M.Ch. (Neuro Surg.), Madurai
Doctor of Medicine (Pathology)	—M.D. (Pathology), Madurai"

[No.V.11015/9/73-MPI]

Km. SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1973

का. आ. 2133.—वायुयान नियम 1937 के नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा उस समय की अवधि को बढ़ा कर 22 जुलाई, 1973 करती है जिसके कि बीच भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना सं. ए. वी. 15013/20/73-ए, दिनांक 1 जून, 1973, द्वारा नियुक्त किये गये जांच न्यायालय से आशा की जाती है कि वह उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी जांच का कार्य समाप्त कर लेगा और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे देगा।

[फा. सं. ए. वी. 15013/20/73-ए.]

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th July, 1973

S.O. 2133.—In exercise of the powers conferred by rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby extends up to the 22nd July 1973, the period of time within which the Court of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation by notification No. Av. 15013/20/73-A dated 1st June, 1973, will be expected to complete its inquiry into the matters specified in the notification mentioned above and report to the Central Government.

[File No. Av. 15013/20/73-A]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1973

का. आ. 2134.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1111, दिनांक 19 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में, स्तम्भ 1 में 'निदेशक, वायुक्षेम' से संबंधित तथा स्तम्भ 2 में तद्नुरूपी प्रविष्टियों के पश्चात् स्तंभ 1 व 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"क्षेत्रीय निदेशक	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 76, 77, 78, 79, 82, 89."

[फा. सं. ए. वी. 11016/1/73-ए./ए. आर./1937(3)/1973]

New Delhi, the 19th July, 1973

S.O. 2134.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, No. S.O. 1111 dated the 19th February, 1971, namely :—

In the First Schedule to the said notification, after the entry in column 1 relating to the 'Director of Air Safety' and the corresponding entries in column 2, thereof, the following shall respectively be inserted in columns 1 and 2, namely :—

"Regional Director	2, 9, 10, 14, 15, 28, 30, 31, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 76, 77, 78, 79, 82, 89."

[F. No. Av. 11016/1/73-A/AR/1937(3)/1973]

का. आ. 2135.—वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन तथा विमानन मंत्रालय (विमानन विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2305, दिनांक 22 जुलाई, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में 'निदेशक, वायुक्षेम' इस प्रविष्टि के पश्चात् 'क्षेत्रीय निदेशक' यह प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी।

[फा. सं. ए. वी. 11016/1/73-ए./ए. आर./1937(2)/1973]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप सचिव

S.O. 2135.—In pursuance of sub-section (1) of section 8 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Aviation (Department of Aviation) No. S.O. 2305, dated the 22nd July, 1966, namely :—

In the said notification after the entry 'Director of Air Safety', the entry 'Regional Director' shall be inserted.

[F. No. Av. 11016/1/73-A/AR/1937(2)/1973]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 जून, 1973

शुद्धि-पत्र

का. आ. 2136.—दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (2), के 4864 से 4872 तक के पृष्ठों पर प्रकाशित दिनांक 11-11-1972 को भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 3387 में, पृष्ठ 4866 पर विनियम 12 के उपविनियम (2) में "विनियम 14" के स्थान पर "विनियम 19" पढ़िए।

[सं. 5-एम टी. (5)/70]

वी. वी. सुब्रह्मण्यम्, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th June, 1973

ERRATUM

S.O. 2136.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S. O. No. 3387 dated the 11th November, 1972 published at pages 4858 to 4864 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th October, 1972, at page 4859 in sub-regulation (2) of regulation 12 **for** "regulation 14" **read** "regulation 19".

[No. 5-MT(5)/70]

V. V. SUBRAHMANIAM, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

का. आ. 2137.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चल चित्र (सेन्सर) नियमावली, 1958 के नियम 9 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 8 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड से परामर्श करने के बाद, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जुलाई, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक, उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य फिर से नियुक्त किया है :—

1. श्री टी. नीलकन्तन
2. श्रीमती राँन्द्रा वैलासम
3. श्री पकाला सूर्य नारायण राव
4. श्री मोहम्मद युसुफ कोकण
5. श्री एम. गोविन्दन
6. श्रीमती सी. एल. मीनाक्षी अम्मा
7. श्री पी. वी. चलपतेश्वर राव
8. श्रीमती मेरी क्लबवाला जादव
9. श्री पी. के. रामलिंगम
10. श्री जी. वरदप्पा
11. श्रीमती आर. सुवर्ण
12. श्रीमती पी. वी. भागीरथी
13. श्रीमती बर्था लोबो
14. श्रीमती इन्दिरा डी. कोठारी
15. श्रीमती मालती चेन्दूर
16. श्री सी. आर. शर्मा
17. श्रीमती राजी रंगाचारी
18. श्रीमती पद्मिनी अचुता मेनन
19. श्रीमती एन. एस. मणि
20. डा. एस. विजयालक्ष्मी
21. श्रीमती लीला पार्थसारथी
22. कुमारी पी. शान्ताबाई
23. श्रीमती एम. लीलावती
24. श्रीमती सरोजिनी वरदम्पन
25. श्रीमती रोहिणी कृष्णचन्द्र
26. डा. (कुमारी) सी. एम. लीलावती
27. श्रीमती हेमलता अजनेयुलु
28. श्रीमती सारा सैयद युसुफ
29. श्रीमती जी. दुबे
30. श्रीमती पद्मा सदानन्दम्

[सं. एफ. 11/4/72-एफ. सी.]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th June, 1973

S.O. 2137.—In exercise of the powers conferred by Section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952, and sub-rule (3) of rule 8 read with sub-rule (2) of rule 9 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government hereby reappoints the following persons after consultation with the Central Board of Film Censors, as members of the Advisory Panel of the said Board at Madras with effect from 1st July, 1973 upto 30th September, 1973 :—

1. Shri T. Neelakanthan
2. Smt. Soundra Kailasam
3. Shri Pakala Suryanarayana Rao
4. Shri Mohd. Yousuf Kokan
5. Shri M. Govindan
6. Smt. C. L. Meenakshi Amma
7. Shri P. V. Chalapatheswara Rao
8. Smt. Mary Clubwala Jadhav
9. Shri P. K. Ramalingam
10. Shri G. Varadappa
11. Smt. R. Suvarna
12. Smt. P. V. Bhagirathi
13. Smt. Bertha Lobo
14. Smt. Indira D. Kothari
15. Smt. Malati Chendur
16. Shri C. R. Sarma
17. Smt. Raji Rangachari
18. Smt. Padmini Achutha Menon
19. Smt. N. S. Mani
20. Dr. S. Vijayalakshmi
21. Smt. Leela Parthasarathi
22. Kumari P. Shanta Bai
23. Smt. M. Leelavathi
24. Smt. Sarojini Varadappan
25. Smt. Rohini Krishnachandra
26. Dr. (Miss) C. M. Leelavati
27. Smt. Hemlata Anjaneyulu
28. Smt. Sara Syed Yusuff
29. Smt. G. Dubey
30. Smt. Padma Sadanandam

[F. No. 11/4/72-FC]

का. आ. 2138.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 जुलाई, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का फिर से सदस्य नियुक्त किया है :—

1. श्री बी. आर. चोपड़ा
2. श्रीमती वीना दुग्गल
3. श्रीमती सुरेन्द्र गुप्त
4. श्री पी. सी. मैथ्यू
5. श्रीमती एम. नसरुल्लाह
6. श्री बी. एन. सरकार
7. श्री ए. एल. श्रीनिवासन
8. श्री सी. आर. सुन्दरम

[फा. संख्या 11/6/72-एफ. सी.]

S.O. 2138.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 the Central Government hereby re-appoints the following persons as members of the Central Board of Film Censors with effect from 1st July, 1973 upto 30th September, 1973 :—

1. Shri B. R. Chopra
2. Smt. Veena Duggal
3. Smt. Surrinder Gupta
4. Shri P. C. Mathew
5. Smt. M. Nasrullah
6. Shri B. N. Sircar
7. Shri A. L. Srinivasan
8. Shri C. R. Sundaram

[F. No. 11/6/72-FC]

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1973

का. आ. 2139.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा श्री डेविड अब्राहम को तत्काल से 30 सितम्बर, 1973 तक, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है।

[फा. संख्या 11/6/72-एफ. सी.]

हरजीत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 7th July, 1973

S.O. 2139.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952, the Central Government hereby appoints Shri David Abraham as member of the Central Board of Film Censors with immediate effect upto 30th September, 1973.

[F. No. 11/6/72-FC]
HARJIT SINGH, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1973

आदेश

का. आ. 2140.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राज फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी, रामगंज मण्डी के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स राज फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी, रामगंज मण्डी के प्रबन्धतंत्र की उनकी सासल खेड़ी चूना पत्थर खानों में नियोजित श्री नानूराम, पत्थर कर्तक को 16 मई, 1970 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं. एल-29012(22)/73-एल. आर.-4]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 27th June, 1973

ORDER

S.O 2140.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relations to management of Raj Flooring Stone Company, Ramgunjmandi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Raj Flooring Stone Company, Ramgunjmandi in stepping Shri Nanuram, Stone Cutter employed at their Satalkhedi Lime Stone Mines from work with effect from the 16th May, 1970 was justified? If not, to what relief is he entitled ?"

[No. L-29012(22)/73-LR-IV]

नई दिली, 13 जुलाई, 1973

आदेश

का. आ. 2141.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आनन्द इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1967 (1967 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या आनन्द इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के प्रबंधतंत्र की श्री इश्तियाक हुसैन काजमी, निरीक्षक, कानपुर की सेवाओं को 30 जून, 1972 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[फा. सं. एल 17012/4/73-एल आर 1]

ORDER

New Delhi, the 13th July, 1973

S.O. 2141.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Anand Insurance Company Limited, Kanpur and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Anand Insurance Company Limited, Kanpur, in terminating the services of Shri Ishtiaq Hussain Kazmi, Inspector, at Lucknow with effect from the 30th June, 1972 is justified? If not, what relief he is entitled to ?"

[F. No. L. 17012/4/73-LR. I]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1973

का. आ. 2142.—यतः, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1413 तारीख 11 अप्रैल 1967 द्वारा गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के. के. सरकार को 23 जून, 1973 से उक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ।

[फा. सं. एस-11025/17-एल. आर. 1(1)]

New Delhi, the 18th July, 1973

S.O. 2142.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the presiding officer of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 1413 dated the 11th April, 1967 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri K. K. Sarkar as the presiding officer of the said Central Government Industrial Tribunal with effect from the 23rd June, 1973.

[F. No. S. 11025/17/73-LR. I. (i)]

का. आ. 2143.—अतः, का. आ. 1781 तारीख 24 जुलाई, 1961 और का. आ. 2839 तारीख 30 सितम्बर, 1963 के साथ पठित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1954 तारीख 30 जुलाई, 1960 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, धनबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के. के. सरकार को 23 जून, 1973 से उक्त श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ।

[फा. सं. एस-11025/17/73-एल. आर.(2)]

S.O. 2143.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the presiding officer of the Labour Court, Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 1954 dated the 30th July, 1960, read with S.O. 1781 dated the 24th July, 1961 and S.O. 2839 dated the 30th September, 1963 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri K. K. Sarkar as the presiding officer of the said Labour Court with effect from 23rd June, 1973.

[F. No. S. 11025/17/73-I.R.I.(ii)]

S.O. 2144.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Gujarat, Ahmedabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oil and Natural Gas Commission, Ahmedabad Project Sabarmati, Ahmedabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th July, 1973.

BEFORE SHRI INDRAJIT G. THAKORE, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 6 of 1971

BETWEEN

The Employers in relation to the Management of Oil & Natural Gas Commission, Ahmedabad Project, Sabarmati, Ahmedabad.

AND

Their Workmen.

In the matter of non-regularisation of contingent telephone operators.

Appearances :

Shri D. C. Gandhi—for the Commission.

Shri P. S. Chari with Shri J. S. Parashar and Shri S. B. Manjanwal—for the Workmen.

AWARD

This industrial dispute between the employers in relation to the management of Oil and Natural Gas Commission, Ahmedabad Project, Sabarmati, Ahmedabad, and their workmen, has been referred to me for adjudication as Industrial Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment's Order No. L-30011/6/71-LR IV, dated the 8th December, 1971. The dispute relates to a single demand which is mentioned in the schedule to the said order and is as follows :—

"Whether the Management of Oil and Natural Gas Commission, Ahmedabad Project, Sabarmati, Ahmedabad Is justified in denying the benefits that are admissible to the regular employees of the Commission to Sarvashri Ashok Kaduskar, Bhikha Bhai Thakar, S. P. Methani, Miss P. A. Mary, Shri Bipin R. Rabkar, with effect from the respective dates of appointment of the employees concerned ? If not, to what relief and from what date are they entitled ?"

In support of the demand, the union has submitted that out of the five workers concerned, Shri Ashok Kaduskar, Shri Bhika Bhai Thakar and Shri S. P. Mehtani were employed on

1-2-1969, Miss P. A. Mary on 18-12-1969 and Shri Bipin R. Tabkar on 1-7-1969; that the first four workers were employed through the Employment Exchange; that they have long back completed more than 240 days of their service and they are still treated as workcharged employees and not regularised. The union has submitted that the Group Gathering Station and other telephone exchange on which they are employed, is of a permanent nature; that they are not temporary installations; that the fact that the said employees are on the said installations for about 3 years shows that the same is of permanent nature; that they are regularly attending on the said installation as regular employees and they are not workcharged employees; that their work is also not of casual nature; that in the circumstances denying them the benefits that are admissible to the regular employees is an act of grave injustice. The union has submitted that under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, the management are required to define the conditions of service; that there is no standing order in respect of workcharged employees; that if these are workcharged employees their conditions of service must be formally defined; that the management is not entitled to treat them as workcharged employees and must be directed to treat them as permanent employees.

The company in their written statement have denied many allegations made by the union. It has submitted that the employees concerned in the reference were taken in employment on workcharged basis and by the terms of appointment they have no right to claim the benefit of regular employees and that looking to the terms of their appointment the demand is not legally maintainable. It has further been submitted that there are no permanent posts so far created by the Commission against which the employees can be absorbed as regular employees; that till the permanent posts are created by the Commission or the permanent posts become vacant there can be no question of absorbing the employees as regular employees or on regular basis and that the demand should, therefore, be rejected. It has further been submitted that the demand involves a question of promotion; that the considerations for employing persons on workcharged basis are different from those for employing the persons on permanent or regular basis; that the qualifications, suitability, experience etc. were scrutinised and judged vis-a-vis employees on temporary or workcharged basis and that the same were not considered vis-a-vis the employment on permanent or regular basis; that in the circumstances it would not be just and appropriate to direct the Commission to absorb them on regular or permanent basis.

The stand taken in the written statement hardly seems to be proper in a dispute of this kind. It may be that they were taken in employment on workcharged basis and therefore by the terms of appointment they may have no right to claim the benefits of regular employees but that is the very reason why this dispute is raised. If persons are employed as workcharged employees when, in fact, the work on which they are employed, is of a permanent nature, that itself would be a proper ground for interference by this Tribunal. The terms of appointment also would be irrelevant. The reply suggests a complete ignorance of the scope and functions of industrial adjudication. Again, it is stated that at the time of their appointment the considerations for employing them and the qualifications for employing them were seen vis-a-vis those of the temporary or workcharged employees but no effort is made to indicate what the qualifications etc. are vis-a-vis permanent employees. The reply of the Commission makes no effort to rebut the allegations that the Commission could not employ these persons as workcharged employees. It also makes no effort to reply to their allegation that the work on which they were employed was work of a permanent nature and they were therefore wrongly employed as workcharged employees. The reply of the Commission leaves much to be desired and it does not meet the case made out by the workmen in their statement of claim. An affidavit has been filed before me by one Shambhu Prasad Mithani which, inter alia, states how he was selected and that he has been continuously working as telephone operator ever since he was appointed; that he had been doing all the regular duties of a telephone operator; that the nature of work performed by him is also of a permanent nature; that there is only one telephone exchange at GGS-2 which is a permanent installation and there are no other ONGC telephone exchange in the area. He has also stated that Shri Ashok Kaduskar, Shri Bhika Bhai Thakkar and Shri Bipin R. Thakkar are also performing the same duties as performed by him and other telephone operators. An affidavit has also been filed by Miss Mary who is working as a telephone operator at ONGC office Chand Kheda which also, inter alia, states that the nature of work performed by her is of permanent type and there is no difference between the duties performed by her and other telephone operators who are regular.

There does not appear to me any doubt whatsoever that the duties performed by these persons are similar to the duties performed by telephone operators and that the work which they are doing is of a permanent nature. After the reference was made an agreement has been arrived at between the Oil & Natural Gas Commission and ONGC Employees' Mazdoor Sabha regarding regularisation of casual/contingent/workcharged/ad hoc employees who have been working in the Western region for a considerable period. Under the same, the ONGC has agreed to create a total of 141 regular posts in various trades and this includes the posts of 6 telephone operators. It has also further filed a written statement before me inter alia in which they have stated that a settlement has been arrived at between the Chairman, Oil & Natural Gas Commission and the Oil & Natural Gas Commission Employees' Mazdoor Sabha whereby the Oil & Natural Gas Commission has agreed to create 141 regular posts in various trades including the 6 posts of telephone operators and the persons covered in this reference are also covered under the said settlement, dated 14-4-1972 and that out of 6 persons in the settlement 5 are also covered in this reference; that they are therefore following the further procedure for regularising the posts of telephone operators under its existing rules, i.e., character verification, police record, medical examination etc., that since the said settlement has been arrived at with the majority union I should only make an award in terms of the said settlement particularly when a number of other persons are also involved. The settlement itself relied upon by the Commission conclusively shows that there was necessity of 6 permanent posts of telephone operators. I would therefore, be perfectly justified in regularising the posts of the 5 telephone operators before me subject to the terms laid down therein. In fact, in view of that settlement the demand must be granted.

The other question is the date from which these persons should be regularised and the conditions on which they should be regularised. The agreement is silent as to the date. The practice, according to the Commission, is to regularise the employees from the date they were regularised and the Commission desires that I should not pass any other order.

The demand on behalf of these workmen was made by the ONGC Employees' Union of whom they are members and when their request was turned down they brought it to the notice of the assistant Labour Commissioner (Central) by a letter, dated 17th April, 1971, and called for his intervention. The conciliation meeting was called by him on 30th April, 1971. On failure this reference has been made on 8-12-1971. Out of these persons, 3 of them were appointed on 1-2-1969, one of them on 18-12-1969 and one of them on 1-7-1969 more than four years back. In the circumstances of the case, I do not think I would be justified in directing that they be regularised prospectively from the date the enquiry etc. is over or from the date when they entered into an agreement with the majority union of which they are not the members. Their case was being agitated by the ONGC Employees' Union very much earlier. The matter had even gone in conciliation and there hardly appears to be any justification when the work for which they were employed was of a permanent nature for continuing them as workcharged employees. However, I do not think I would be justified in dispensing with the necessary procedure before making persons regularised, i.e., character verification, police records, medical examination, etc. I am, however, given to understand that with considerable effort the character verification and police records have already been completed in the case of these persons and what remians is only medical examination. I, therefore, direct as follows :—

(1) That the Commission shall within one month from the date this award becomes enforceable complete character verification medical examination and other necessary procedure.

(2) Subject to the above, these persons be regularised. Shri Ashok Kaduskar, Shri Bhika Bhai Thakar and Shri S. P. Mehtani with effect from 1st October, 1971, and Miss P. A. Mary and Shri Bipal R. Tabkar with effect from 1st April, 1972.

I further direct the Oil & Natural Gas Commission to pay Rs. 100 (Rupees one hundred only) to the ONGC Employees' Union, Ahmedabad, as and by way of costs. The amounts payable under this award to be paid within two months from the date this award becomes enforceable.

[No. L-30011/6/71-LR-IV.]

INDRAJIT G. THAKORE, Presiding Officer.

Ahmedabad, 30th June, 1973.

New Delhi, the 19th July, 1973

S.O. 2145.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the establishment of Mines and Pale Palletisation Plant of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour, Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1973.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/3 of 1973

Employers in relation to the establishment of Mines and Pale Palletisation Plant of Messrs. Chowgule and Company Private Limited Mormugao Harbour, Goa.

AND

Their Workmen.

Present :

Shri N. K. Vani, Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers : Shri G. D. Shirodkar, Personnel Manager.

For the workmen : Absent.

Industry : Iron Ore Mines **State :** Goa, Daman and Diu.

Bombay, the 30th June, 1973

AWARD

By order No. L-29011/1/73-LR. IV dated 24th March, 1973, the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the establishment of Mines and Pale Palletisation Plant of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour Goa and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule as mentioned below :—

"SCHEDULE

Whether the following demands of the workmen employed in Mines and Pale Palletisation Plant of Messrs. Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour, Goa are justified, namely :—

(i) Additional bonus ; and

(ii) Revision of pay scales.

If so, to what relief are the workmen entitled and from what date ?"

2. The facts giving rise to this reference are as follows :—

(i) The Chowgule Employees Union, Vasco-da-Gama raised an industrial dispute. The Assistant Labour Commissioner (C), Vasco-da-Gama tried to bring about conciliation between the company and the employees but in vain. He therefore submitted his failure of conciliation report to the Government of India, who in turn referred this dispute for adjudication.

3. After the receipt of the reference notices were issued to the parties to appear before me and file their say.

4. Both the parties amicably settled the dispute and filed the settlement at Ex. 1/EW before this Tribunal for passing award in terms of the same.

5. Reference was fixed for hearing on 25-6-1973 after the settlement was produced. On 25-6-1973 the company asked for adjournment and the Union remained absent. The company was given time till 29-6-1973 and requested to inform the Union that reference was adjourned for hearing on 29-6-1973.

6. Accordingly the company informed the Union that the case was fixed on 29-6-1973 by letter Ex. 3/E. In spite of this intimation the Union has remained absent.

7. Shri G. D. Shirodkar, Personnel Manager has given evidence at Ex. 2/E on 29-6-1973. His evidence proves that there was settlement between the company and the Union. He indentifies the signatures of Messrs. P. B. R. Rao and D. P. Sinha representing the management. He has also signed the settlement. He also indentifies the signature of Shri Gerald Pereira and others representing the employees. He indentifies the signatures of witnesses i.e. S/shri S. V. Natekar and A. K. Patil.

8. From the evidence of Shri Shirodker, Personnel Manager I am convinced that there was amicable settlement between the partles during the pendency of reference, referred to this Tribunal.

9. On going through the Settlement Ex. 1/EW it is clear that pay scales of all the employees have been revised as mentioned in the settlement. Bonus has been also given. I am satisfied from the settlement that it is in the interest of both the parties. Terms of settlement are quite fair and reasonable. The same is also voluntary. I therefore accept the settlement and pass the award in terms of the settlement.

10. In the end I pass the following order :—

ORDER

(i) Award in terms of Settlement Ex. 1/EW is made.

(ii) Settlement Ex. 1/EW is to form part of the Award.

(iii) Parties to bear their own costs.

Ex. 1/EW

Memorandum of agreement under Section 2(p) and Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947, between the Management of Messrs. Chowgule & Company Private Limited, Mormugao Harbour, and their workers employed at Company's Mines in Goa, represented by Chowgule Employees' Union (CITU), Vasco-da-Gama

Present

Representing Management :

Mr. P. B. R. Rao,
General Manager,
Chowgule & Co. Pvt. Ltd.,
Mormugao Harbour,
Mr. G. D. Shirodkar,
Personnel Manager,
Chowgule & Co. Pvt. Ltd.,
Mormugao Harbour,
Mr. D. P. Sinha,
Labour Officer,
Chowgule & Co. Pvt. Ltd.,
Mormugao Harbour,

Representing the workmen :

Mr. Gerald Pereira,
General Secretary,

Chowgule Employees' Union,
Mr. C. M. Prabhu,
Vice-President,
Chowgule Employees' Union,
Mr. B. K. Pawar,
Vice-President,
Chowgule Employees' Union,
Mr. S. S. Naik,
Assistant Secretary,
Chowgule Employees' Union,
Mr. K. S. Habbibulla,
Executive Committee Member,
Chowgule Employees' Union,
Mr. S. S. Mayekar,
Member, General Council,
Chowgule Employees' Union,
Mr. Pandurang V. Dalvi,
Assistant Secretary,
Chowgule Employees' Union.
Mr. N. S. Kudke,
Assistant Treasurer,
Chowgule Employees' Union.

Short recital of the case: In its letter dated 3rd October 1972, the Union demanded for revision of payscales, bonus, dearness allowance, uniform additional increments, extra services increment, a flat increase of Rs. 70/-, gratuity, uniforms and canteen facilities. Immediately after a week almost, the Union submitted another letter dated 9th October 1972 whereby it further demanded for confirmation of workers who have put in more than 6 months' continuous service, promotions to all the workers strictly on seniority basis and supply of furnished quarters or in alternative substantial amount of house rent allowance. The disputes were taken up for conciliations/discussions by the Assistant Labour Commissioner, Vasco-da-Gama on 16-12-72 and 20-12-72. Subsequently, the Union vide its letter dated 1st November, 1972, further demanded immediate filling up of posts/vacancies and granting promotions to the employees strictly on the basis of seniority and granting variable dearness allowance linked with the rise in cost of living. It also demanded certain other things, vide this letter which were a repetition of the earlier demands already covered above.

On 11th December, 1972, the Union gave a strike notice for bonus and on 14th December, 1972 a strike notice for payscales, uniforms and washing allowance, dust allowance, confirmation of workers and recognition of Union. The Conciliation Officer, Vasco-da-Gama, submitted his failure reports on 24th December, 1972 and 10th January, 1973 respectively. Nevertheless, the Management agreed to keep the doors open for mutual negotiations. Accordingly, discussions were held on several occasions and the following mutual settlement was arrived at:

TERMS OF SETTLEMENT

1. Demand for revision in payscales, flat increase, service increments, dearness allowance and uniform additional increments.

(a) It is agreed between the parties that with effect from 1st January, 1973, the scales of pay of permanent employees working in the Company's Mining Establishments in Goa will be revised as given below :—

Old basic pay scales excluding Fixed D.A.	Revised consolidated (Basic +F.D.A.) scales.
1. 75-2-85	140-5-165-5½-192½-6-222½
2. 80-2-90	150-5½-177½-6-207½-7-242½
3. 85-2-95-3-110	160-6-190-6½-222½-7½-237½
4. 95-2-105-3-120	185-6½-217½-7½-255-8½-272
5. 110-3-125-4-145	210-7½-247½-8½-290-9½-309
6. 130-5-180	230-8½-272½-10-322½-12-346½
7. 155-6-185-7-220	265-10-315-12-375-13½-402
8. 170-8-210-10-260	280-10½-1332½-12½-395-15-425
9. 215-10-285-15-330	330-12½-392½-15-467½-17-501½
10. 255-10-275-15-395	370-15-445-10-545-22-589
11. 325-15-575	445-20-545-22-655-25-705
12. 350-20-450-25-575	480-21-585-25-710-30-770
Clerical:—	
I. 300-15-375-20-575	400-15-475-20-575-25-700
II. 190-12-250-15-400	280-12-340-15-415-20-515
III. 120-10-170-12-290	210-10-260-12-320-15-395
IV. 100-7-135-10-185	175-7-210-10-260-12-284

Note: The above consolidated payscales agreed to be brought into force from 1-1-1973 are inclusive of basic pay and fixed D.A. at the All India Consumers Price Index No. 166 (base: 1949=100).

(b) It is further agreed between the parties that all categories of employees in the old basic scales of pay will be fietted in the above corresponding new consolidated scales of pay as from 1-1-1973.

(c) It is agreed between the parties that while fitting the workers into the new consolidated (basic+F.D.A.) scales of pay, an addition of flat increase of Rs. 15 will be made to basic pay, Fixed D.A. and personal pay/personal allowance, if any, as on 31-12-1972. To this amount, the increment if due on 1-1-1973 in the old scales of pay which he was already enjoying, will be added. Further the difference in increments in the old scales and revised scales will also be added to the above amount. If the total amount so arrived at falls below the minimum of the new payscales the worker will be fitted at the starting step of the new payscale; if the amount is higher than the starting step of new scale of pay but falls in between any two steps, the worker concerned will be fitted at the next higher step; if the amount corresponds to any step in the new payscale, the worker concerned will be fitted at that step.

(d) It is agreed that the workers fitted in the new scales of pay, as per sub-clause (c) above will draw their next increment in the scales of pay on 1-1-74.

(e) It is agreed that V.D.A. for rise and fall in the All India Consumers Price Index beyond No. 166 will continue to be paid to the workers in the manner as determined by the Central Wage Board for Iron Ore Mining Industry as at present.

II. It is further agreed that if during the currency of this settlement, the Government or a Wage Board or any Authority prescribes basic scales of pay for mining workers and if such directive or Award is binding on the Company, then corresponding basic pay will be worked out by separating the element of Fixed D.A. from the then existing consolidated pay on the following basis:

For consolidated pay The element of Fixed D.A. to be separated to arrive at basic pay.	
Upto Rs. 209	Rs. 55
Rs. 210 to Rs. 364	Rs. 60
Rs. 365 to Rs. 469	Rs. 65
Rs. 470 and above	Rs. 70

III. The Management agrees to fix all confirmed employees in daily scales of pay, in monthly scales of pay w.e.f. 1-1-73 with all benefits applicable to monthly rated employees.

IV. **Bonus:**

For the financial year 1971-72, the Company has already offered to its workers a bonus of 8.33 per cent of their salaries/wages as required under the provisions of the Bonus

Act as amended. The Union on behalf of the workmen agrees to accept the said payment as in full and final settlement for the financial year 1971-72.

V. As a gesture of goodwill, the Management agrees to pay to workers who are on the rolls of the Company on the date of this settlement, an ex-gratia payment equal to 3.67 per cent of the gross salary/wages drawn by the employees during the year 1-4-1971 to 31-3-1972 excluding the payment made under clause 7 of the settlement dated 24-2-1972 and the bonus paid during the year 1971-72. It is further agreed that this ex-gratia payment will not attract any other benefits such as, provident fund, employees' State Insurance Contributions, bonus etc.

VI. **Gratuity :**
Since the Management has already implemented the payment of Gratuity Act, 1972 with effect from 16th September, 1972, the Union accepts the implementation of the Payment of Gratuity Act, 1972.

VII. **Canteen Facilities :**
In view of the Clause No. II. 2 of the Annexure to the Settlement dated 24-2-1972, the Union agrees not to press this demand.

VIII. The Union agrees to withdraw all other demands mentioned in the short recital of this settlement.

IX. The Union strongly contended for the dust allowance for the workers in the Mining Establishment. The Management refused to concede to this demand on principle. The Union has, therefore, withdrawn the demand for dust allowance also.

X. Although the new payscales and fitments are to be effective from 1-1-1973, the Management agree to pay an amount of Rs. 15, representing the flat increase, for the month of December, 1972 to all permanent workers who are on the rolls on the date of this agreement.

XI. It is agreed between the parties that the fitment as the revised scales of pay will be given effect in the paysheets for the month of May 1973 and all arrears arising out of this settlement will be paid along with the pay for May, 1973. Bonus due and ex-gratia payment of 3.67 per cent will, however, be paid along with the salary of April, 1973.

XII. The Company will issue individual slips to each workman showing therein his revised pay and allowance with effect from 1-1-1973.

XIII. The Management is further pleased to accord formal recognition as provided under the Code of Discipline to Chowgule Employees' Union.

XIV. It is agreed between the parties that in respect of all points covered in this settlement and the settlement dated 24-2-1972 which have the effect of modifying any provisions of the existing standing orders of the Company, the parties hereby agree to jointly approach before 15-7-73, the Certifying Officer to incorporate the said changes in the existing Standing Orders.

XV. The Union on behalf of the workmen without prejudice to their rights and contentions, assures the Management good behaviour on the part of the workmen and that they would carry on their work in the customary manner, on resumption.

XVI. The Union on behalf of workmen agrees to honour the settlement dated 24-2-1972.

XVII. It is agreed between the parties that this settlement will come into force with effect from 1-1-1973 and will remain binding on the parties till 31-12-1976.

XVIII. It is agreed between the parties to jointly approach the Asstt. Labour Commissioner(C), Vasco-da-Gama to get this settlement duly registered under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 before the 15th April, 1973.

XIX. It is further agreed between the parties to jointly request the Central Government Industrial Tribunal to whom the disputes have been referred for adjudication, to give a consent award in terms of this settlement.

Signature of the parties :

Sd/-
(1) (P. B. R. Rao)

Sd/-
(2) G. D. Shirodkar)

Sd/-
(3) (D. P. Sinha)

Sd/-
(1) (Gerald Pereira)

Sd/-
(2) (C. M. Prabhu)

Sd/-
(3) (B. K. Pawar)

Sd/-
(4) (S. S. Naik)

Sd/-
(5) (K. S. Habbibulla)

Sd/-
(6) (S. S. Mayekar)

Sd/-
(7) (Pandurang V. Dalvi)

Sd/-
(8) (N. S. Kudke)

Witnesses :—

Sd/-
1. (S. V. Natekar)

Sd/-
2. (A. K. Patil)

Mormugao Harbour,
Dated : 29-3-1973.

[No. L-29011/1/73-LR. IV]
N. K. VANI, Presiding Officer,
S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1973

का. आ. 2146.—कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3क की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 4008, तारीख 21 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 15, 16 और 17 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

15. श्री के. पी. सिंह, एरिया महाप्रबंधक, एरिया सं. 5, डाकखाना भौंरा, (जिला धनबाद) ।

16. श्री सुबोध राय, लेखा-नियंत्रक, सी. एम. ए. संकटौरिया, बिलासपुर ।

17. श्री एस. सी. मलिक, मुख्य लेखा-अधिकारी, एस. सी. डी. सी. शाखा रांची ।

[सं. 1-11013(12)/71-पी. एफ. 1]

New Delhi, the 11th July, 1973

S.O. 2146.—In exercise of the powers conferred by clause (e), sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4008, dated the 21st November, 1972, namely :—

In the said notification for the entries against serial numbers 15, 16 and 17, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

15. Shri K. P. Singh, Area General Manager, Area No. V. P. O. Bhowra (District Dhanbad).

16. Shri Subodh Roy, Controller of Accounts, C. M. A. Sanctoria, Dishergarh.

17. Shri S. C. Mallik, Chief Accounts Officer, N. C. D. C. Branch, Ranchi.

[No. I. 11013(12)/71-PF. I]

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1973

का. आ. 2147.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि गवर्नमेंट ऑपियम एण्ड एल्कालायड वर्क्स, गाजीपुर के कर्मकारों को, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबंधित प्रसुविधाएं जैसी सारतः प्रसुविधाएं प्राप्त हैं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2325, तारीख 18 जून, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा उल्लिखित कर्मशाला को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित हैं, एक और वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[फा. सं. एस-38017/15/72-एच आई]

New Delhi, the 13th July, 1973

S.O. 2147.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur, are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2325, dated the 18th June, 1972, the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1973, upto and inclusive of the 30th June, 1974.

[F. No. S-38017/15/72-HI]

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1973

का. आ. 2148.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2478, तारीख 19 जून, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार नेशनल इंस्ट्रूमेंटस् लिमिटेड कलकत्ता की उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि से एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

[फा. सं. एस-38017(35)/72-एच. आई.]

New Delhi, 13th July, 1973

S.O. 2148.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2478, dated the 19th June, 1972, the Central Government hereby exempts the National Instruments Limited, Calcutta, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification.

[F. No. S-38017(35)/72-HI]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1973

का० आ० 2149—कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1736, तारीख 19 मई, 1972 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, नेवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, कोयला खान बोनस स्कीम, आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम, राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम, असम कोयला खान बोनस स्कीम और कोयला खान कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है और निदेश देती है कि ये पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान असम, नागालैंड, तमिल नाडु तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में, कोयला खानों के संबन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :—

1. श्री एस० ए० वेंकटरेअन	आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि
2. श्री एन० कल्याणसुन्दरम्	ज्येष्ठ वित्त अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि।
3. श्री आर० कुमार	उप आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि।
4. एस० ए० मोएत्र	प्रादेशिक आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि।
5. श्री बी० के० सिन्हा	,,
6. श्री आर० के० वर्मा	,,
7. श्री ओ० पी० शर्मा	,,
8. श्री एस० पी० शर्मा	,,
9. श्री ए० बी० प्रसाद	,,
10. श्री पी० एन० कक्कर	,,
11. श्री राजेन्द्र लाल	,,
12. श्री एल० पी० सिन्हा	सहायक आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि।
13. श्री ए० चौधरी	वित्त अधिकारी, कोयला खान भविष्य निधि।
14. श्री के० भास्करण	सहायक वित्त अधिकारी कोयला खान भविष्य निधि
15. श्री ए० एन० वेधनाथन	,,
16. श्री ए० एन० भट्टाचार्जी	,,

17. श्री जे० सी० शोम	कोयला खान भविष्य निधि
18. श्री एन० सी० दत्ता	,,
19. श्री एस० आर० सिंह	,,
20. श्री एल० चन्दर	भविष्य निधि निरीक्षक
21. श्री के० एम० बर्मन	,,
22. श्री पी० के० भट्टाचार्जी	,,
23. श्री एस० के० सक्सेना	,,
24. श्री ओ० पी० अग्रवाल	,,
25. श्री एम० के० सिन्हा	,,
26. श्री आर० के० सरकार	,,
27. श्री एम० एम० कुन्डु	,,
28. श्री जी० आर० भारती	,,
29. श्री पी० एन० सिंह	,,
30. श्री जी० एस० दास	,,
31. श्री के० बी० बहल	,,
32. श्री एल० प्रसाद	,,
33. श्री एस० सी० हजेला	,,
34. श्री ए० के० मुखर्जी	,,
35. श्री एस० सी० राय	,,
36. श्री वी० एन० गुप्ता	,,
37. श्री आर० डी० एन० सिन्हा	,,
38. श्री ए० के० चक्रवर्ती	,,
39. श्री पी० पी० यादव	,,
40. श्री मोहन लाल	,,
41. श्री एम० सी० गलगोटिया	,,
42. श्रीमती इन्दिरा सिंहा	,,
43. श्री के० एन० मिश्रा	,,
44. श्री डी० पी० राय	सचिव

[सं० ए० 12034(14)/73-पी० एफ० 1]

New Delhi, the 18th July, 1973

S. O. 2149:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act 1948 (46 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1736, dated the 19th May, 1972, the Central Government hereby appoints the following officers to be Inspectors for the purposes of the Coal Mines Provident Fund Scheme, Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, Coal Mines Bonus Scheme, Andhra Pradesh Coal Mines Bonus Scheme, Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme, Assam Coal Mines Bonus Scheme and the Coal Mines Family Pension Scheme and directs that they shall in relation to Coal Mines, exercise the powers and perform the functions of Inspectors under the said Act in the States of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Assam, Nagaland, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir, namely:—

1. Shri S.A. Venkatarayan.	Coal Mines Provident Fund Commissioner.
2. Shri N.Kalyanansundaram	Senior Finance Officer, Coal Mines Provident Fund.
3. Shri R. Kumar	Deputy Commissioner, Coal Mines Provident Fund.
4. Shri S.A. Moiz	Regional Commissioner Coal Mines Provident Fund.
5. Shri B.K. Sinha	,,
6. Shri R.K. Verma	,,
7. Shri O.P. Sharma	,,
8. Shri S.P. Sharma	,,
9. Shri A.B. Prasad	,,
10. Shri P.N. Kackar	,,
11. Shri Rajendra Lal	,,
12. Shri L.P. Sinha	Assistant Commissioner, Coal Mines Provident Fund.
13. Shri A. Choudhury	Finance Officer, Coal Mines Provident Fund.
14. Shri K. Bhaskaran	Assistant Finance Officers, Coal Mines Provident Fund.
15. Shri A.N. Baidyanathan	,,
16. Shri A.N. Bhattacharjee	,,
17. Shri J.C. Shome	,,
18. Shri N.C. Dutte	,,
19. Shri S.R. Singh	,,
20. Shri L. Chandar	Provident Fund Inspectors.
21. Shri K.M. Burman	,,
22. Shri P.K. Bhattacharjee	,,
23. Shri S.K. Saxena	,,
24. Shri O.P. Agrawal	,,
25. Shri M.K. Sinha	,,
26. Shri R.K. Sirkar	,,
27. Shri M.M. Kundu	,,
28. Shri G.R. Bharati	,,
29. Shri P.N. Singh	,,
30. Shri G.S. Das	,,
31. Shri K.B. Bahl	,,
32. Shri L. Prasad	,,
33. Shri S.C. Hajela	,,
34. Shri A.K. Mukherjee	,,
35. Shri S.C. Roy	,,
36. Shri V.N. Gupta	,,
37. Shri R.D.N. Sinha	,,
38. Shri A.K. Charkravarty	,,
39. Shri P.P. Yadav	,,
40. Shri Mohan Lal	,,
41. Shri M.C. Galgotia	,,
42. Smt. Indira Sinha	,,
43. Shri K.N. Mishra	,,
44. Shri D.P. Roy	Secretary

[A/12034(14)/73-PF-I]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1973

का. आ. 2150.—यतः मैसूर सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री के. नारासिमहा मूर्ती, सचिव, मैसूर सरकार, सामाजिक कल्याण तथा श्रम विभाग, बंगलौर को श्री आई. पी. मल्लाप्पा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया है,

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार

विभाग) की अधिसूचना संख्या का आ. 2763 दिनांक 27 मई, 1971 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 16 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"श्री के नारासिमहा मूर्ती, सचिव, मैसूर सरकार सामाजिक कल्याण तथा श्रम विभाग, बंगलौर ।"

[फा. सं. यू-16012/12/73-एच. आई.]

New Delhi, the 19th July, 1973

S.O. 2150.—Whereas the State Government of Mysore has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri K. Narasimha Murthy, Secretary to the Government of Mysore, Social Welfare and Labour Department Bangalore to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri I. P. Mallappa ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 16, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri K. Narasimha Murthy,
Secretary to the Government of Mysore,
Social Welfare and Labour Department,
Bangalore.

[File No. U-16012/12/73-HI]

का. आ. 2151.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2964 तारीख 25 जुलाई, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार दामोदर वैली कार्पोरेशन, सब-स्टेशन हावड़ा को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

[फा. सं. एस-38017(63)/72-एच. आई.]

S.O. 2151.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2964, dated the 25th July, 1972, the Central Government hereby exempts the Damodar Valley Corporation sub-station, Howrah from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification.

[F. No. S. 38017(63)/72-HI]

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1973

का. आ. 2152.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनाईटेड ट्रेडर्स, 49, ओल्ड तारागुपेट, बंगलौर-2ए नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(21)/73-पी. एफ. 2]

New Delhi, the 20th July, 1973

S.O. 2152.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in the relation to the establishment known as Messrs United Traders, 49, Old Taragupet, Bangalore-2A have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1972.

[No. S-35019/12/73-PF. II]

का. आ. 2153.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोल्लाटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड 20/2, मथुरा रोड : फरीदाबाद (जिसमें इसका 173 गोल्फ लिंकस, नई दिल्ली स्थित दिल्ली कार्यालय भी सम्मिलित है) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(110)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 2153.—Whereas is appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Rollatainers Private Limited 20/2 Mathura Road, Faridabad including its Delhi Office at 173, Golf Links, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1972.

[No. S. 35019/110/72-PF. II]

का. आ. 2154.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स संघवी ब्रदर्स, 392/97 नरसी नाथ स्ट्रीट, कत्था बाजार, मुम्बई-9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35018(16)/73-पी एफ 2]

S.O. 2154.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sankhvi Brothers, 392/97 Narsi Natha Street, Katha Bazar, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1971.

[No. S. 35018(16)/73-PF. II]

का. आ. 2155.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् श्री जै नारायण ट्रेडस्, कोचीन-2 जिसमें इसकी अस्पताल मार्ग क्वीलन वाली शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन को 30 सितम्बर, 1972 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस. 35019(5)/73-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 2155.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the thirtieth day of September, 1972, the establishment known as Shri Jhai Narain Trades, Cochin-2 including its branches at Hospital Road, Quilon for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(5)/73-PF. II(ii)]

का. आ. 2156.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज, यूनिवर्सिटी कैम्पस, हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं एस-35019(13)/73-पी एफ 2]

S.O. 2156.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Institute of Public Enterprises, University Campus, Hyderabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1972.

[No. S. 35019/13/73-PF. II]

का. आ. 2157.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कामथ एण्ड कम्पनी, 352-54, विट्ठल भाई पटेल रोड, मुम्बई-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के सितम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35018(19)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 2157.—Whereas is appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kamath and Company, 352-54 Vithalbhai Patel Road, Bombay-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1972.

[No. S-35018/19/73-PF. II]

का. आ. 2158.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् मैसर्स एम. एन. मलिक एण्ड ब्रदर्स, 5 लेनिन सारणी (दूसरी मंजिल) कलकत्ता-13, जिसमें इसकी 12/3 पाड्डापुकुर ईस्ट लेन, कलकत्ता-23 पर स्थित शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन को 30 अप्रैल, 1973 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस-35017(2)/73-पी. एफ. 2(2)]

S.O. 2158.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 30th April, 1973 the establishment known as Messrs. M. N Mullick and Brothers, 5, Lenin Sarani (2nd floor) Calcutta-13 including its Branch at 12/3 Paddapukur East Lane, Calcutta-23 for the purposes of the said proviso.

[No. S-35017/2/73-PF. II(ii)]

का. आ. 2159.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी. एम. एजेंसीज बरार हाउस, 239 अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मुम्बई-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35018(21)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 2159.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. B. M. Agencies, Barar House, 239 Abdul Rehman Street, Bombay-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1972.

[No. S. 35018/21/73-PF. II]

का. आ. 2160.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. एन. मलिक एण्ड ब्रदर्स, 5, लेनिन सारणी (दूसरी मंजिल) कलकत्ता-13 जिसमें इसकी 12/3, पाड्डापुकुर ईस्ट लेन कलकत्ता-23 पर स्थित शाखा भी सम्मिलित है नामक से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35017(2)/73-पी. एफ. 2(1)]

S.O. 2160.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. M. N. Mullick and Brothers, 5, Lenin Sarani (2nd floor) Calcutta-13 including its branch at 12/3 Paddapukur East Lane, Calcutta-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisinos of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirtieth day of April, 1973.

[No. S-35017/2/73-PF. II(i)]

का. आ. 2161.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जनवरी, 1972 से दि प्रिसिजन इंजीनियरिंग कम्पनी 7ई लिंडसे स्ट्रीट, कलकत्ता-16 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. एस-35017(1)/73-पी एफ 2(2)]

S.O. 2161.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the 31st January, 1972, the establishment known as the Precision Engineering Company, 7E Lindsay Street, Calcutta-16 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/1/73 PF. II(ii)]

का. आ. 2162.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि इंडस्ट्रियल कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी सिक्का, जामनगर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अगस्त के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(20)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 2162.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Industrial Consumers Co-operative Society, Sikka, Jamnagar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1972.

[No. S-35019/20/73-PF. II]

का. आ. 2163.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एंक्शन फार फूड प्राडक्टस सी-52, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन-2 नई दिल्ली-49 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना में 1972 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस. 35019(11)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 2163.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Action for Food Production, C-52 New Delhi South Extension-II New Delhi-49 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1972.

[No. S-35019/11/73-PF. II]

का. आ. 2164.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फारमर्स नृपतुंग रोड, बंगलौर-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(25)/72-पी. एफ. 2]

S.O. 2164.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Farmers's Forum Nrupatunga Road, Bangalore-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1972.

[No. S-35019/25/73-PF. II.]

का. आ. 2165.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि प्रिसिजन इंजीनियरिंग कम्पनी 7ई लिंडसे स्ट्रीट कलकत्ता-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 की जनवरी के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस 35017(1)/73-पी एफ 2(1)]

S.O. 2165.— Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Precesion Engineering Company, 7E Lindsay Street, Calcutta-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1972.

[No. S-35017/1/73-PF. II(i)]

का. आ. 2166.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेनटैक्स कार्पोरेशन, नया बंगला, एस. वी. रोड, बोरिवली (वेस्ट) मुम्बई-92 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के अक्तूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35018(22)/73-पी एफ 2]

S.O. 2166.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs. Chentex Corporation, Naya Bunglow S. V. Road, Borivli (W) Bombay-92 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1972.

[No. S-35018/22/73-PF. II]

का. आ. 2167.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री जे नारायण ट्रेडस् कोचीन-2, जिसमें इसकी अस्पताल मार्ग, क्वालन वाली शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के सितम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस. 35019(5)/73-भ. नि. 2(1)]
दलजीत सिंह, अवर सचिव

S.O. 2167.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment knows as Shri Jhai Narain Trades, Cochin-2 including its branch at Hospital Road, Quilon have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on *the thirtieth* day of September, 1972.

[No. S. 35019(5)/73-PF. II(i)]
DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1973

का. आ. 2168.—मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा द्वारा यथाअपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किए जाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप स्कीम

1. इस स्कीम का नाम मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है।

2. मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) स्कीम, 1968, में, खण्ड 16 के उपखण्ड (2) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 5-13011/5/72-पी एंड डी]

New Delhi, the 16th July, 1973

S.O. 2168.—The following draft of a scheme further to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (4) of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This scheme may be called the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

2. "In the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, in clause 16, in sub-clause (2), for the word "Board", the word "Chairman" shall be substituted.

[F. No. V-13011/5/72-P&D]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1973

का. आ. 2169.—यतः विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप स्कीम, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं का. आ. 3434, तारीख 30 अगस्त, 1972 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (2), तारीख 28 अक्टूबर, 1972 के पृष्ठ 4926-27 पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य था, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के अवसान होने तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 28 अक्टूबर, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

प्रारूप स्कीम

2. विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में,—

(क) खंड 15 में—

(1) मद (ङ) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ङ) मुख्य मजदूर एव स्टिचर मिस्त्री।

(च) मजदूर एव स्टिचर।";

(2) मद (ज) और (झ) को लुप्त कर दिया जाएगा ;

(ख) अनुसूची 1 में—

(1) मद (छ) और (च) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(छ) मुख्य मजदूर एवं स्टिचर मिस्त्री ।

(च) मजदूर एवं स्टिचर ।" ;

(2) मद (ज) और (झ) को लुप्त कर दिया जाएगा ;

(ग) अनुसूची 2 में, पैरा (क), (ख), (ग) में और पैरा (ङ) के अन्तर्गत उदाहरण में, जहां कहीं भी "मजदूर" शब्द आता है, उस के स्थान पर "मजदूर एवं स्टिचर" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. वी. 15011/4/71-पी. एण्ड डी.]

New Delhi, the 18th July, 1973

S.O. 2169.—Whereas certain draft scheme to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 4926-27 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th October, 1972 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 3434, dated the 30th August, 1972 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of 40 days from the date of publication of that notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th October, 1972 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, —

(a) in clause 15—

(i) for items (e) and (f) the following items shall respectively be substituted, namely :—

"(e) leading mazdoor-cum-stitcher mistry.

(f) mazdoor-cum-stitcher";

(ii) items (h) and (i) shall be omitted;

(b) in Schedule I—

(i) for items (e) and (f) the following items shall respectively be substituted, namely :—

"(e) leading mazdoor-cum-stitcher mistry.

(f) mazdoor-cum-stitcher";

(ii) items (h) and (i) shall be omitted ;

(c) in Schedule II in paragraphs (a), (b), (c) and in the example under paragraph (c) for the word "mazdoor" wherever it occurs, the words "mazdoor-cum-stitcher" shall be substituted.

[No. V. 15011/4/71/P&D]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1973

का. आ. 2170.—यतः, विशाखापत्तनम् डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप स्कीम, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 743, तारीख 27 फरवरी, 1973 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 10 मार्च, 1973 के पृष्ठ 1129-1130 पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य था, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ,

और यतः, उक्त राजपत्र जनता को 10 मार्च, 1973 को उपलब्ध करा दिया गया था ,

और यतः, उक्त प्रारूप पर कोई आक्षेप या सुझाव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ;

यतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1)इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम् डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. विशाखापत्तनम् डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"33-जब नियुक्ति के पश्चात् काम उपलब्ध न किया जाए तब मजदूरी का संदाय—जब आरक्षित पूलका कोई कर्मकार स्वयं को काम के लिए प्रस्तुत करे और किसी कारण से वह काम, जिसके लिए वह उपस्थित हुआ हो, प्रारंभ न हो सका हो या आगे न बढ़ सका हो तब वह इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह सम्पूर्ण पारी में उपलब्ध रहेगा और अनुकल्पी नियोजन दिया गया तो उसे स्वीकार करेगा, मजदूरी की साधारण दर का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण—'मजदूरी की साधारण दर' पद से आधारित कालानुपाती मजदूरी दर और भत्ते, यदि कोई हों, अभिप्रेत हैं ।"

[फा. सं. वी. 15013/4/73-पी एण्ड डी]

New Delhi, the 19th July, 1973

S.O. 2170.—Whereas certain draft scheme to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1129-1130 of the Gazette of India, part-II, section 3, sub-section (ii), dated the

10th March, 1973 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 743, dated the 27th February, 1973 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 10th March, 1973;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause 33 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 the following clause shall be substituted, namely:—

"33 Payment of wages when work is not made available after engagement.—When a worker in the reserve pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed, he shall be entitled to ordinary rate of wages subject to the condition that he is available throughout the shift and accepts alternative employment, if provided.

Explanation.—The expression 'ordinary rate of wages' means the basic time-rate wage plus allowance, if any."

[File No. V. 15013/4/72/P & D]

का. आ. 2171.—यतः विशाखापत्तनम् अराजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 744, तारीख 27 फरवरी, 1973 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखण्ड (2) तारीख 10 मार्च, 1973 के पृष्ठ 1130 पर प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य था, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्त होने तक आक्षेप या सुझाव मांगे गये थे,

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 10 मार्च, 1973 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप तथा सुझाव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विशाखापत्तनम्, अराजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम) स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :—(1) इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम् अराजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. विशाखापत्तनम् अराजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खंड 29 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"29-जब नियुक्ति के पश्चात् काम उपलब्ध न किया जाए तब मजदूरी का संदाय :—

जब कोई सूची-बद्ध कर्मकार स्वयं को काम के लिए प्रस्तुत करे और किसी कारण से वह काम, जिसके लिए वह उपस्थित हुआ हो, प्रारंभ न हो सके या आगे न बढ़ सका हो तब वह इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह सम्पूर्ण पारी में उपलब्ध रहेगा और अनकल्पी नियोजन दिया गया तो उसे स्वीकार करेगा, मजदूरी की साधारण दर का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण .—'मजदूरी की साधारण दर' पद से आधारिक कालानुपाती मजदूरी दर और भत्ते, यदि कोई हों, अभिप्रेत है।

[सं. वी. 15013/4/72-पी. एण्ड डी.]

S.O. 2171.—Whereas certain draft scheme to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1130 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 10th March, 1973 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. S.O. 744, dated the 27th February, 1973 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

And whereas no objections and suggestions have been public on the 10th March, 1973.

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For clause 29 of the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 the following clause shall be substituted, namely :—

"29. Payment of wages when work is not made available after engagement.—When a listed worker presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed, he shall be entitled to ordinary rate of wages subject to the condition that he is available throughout the shift and accepts alternative employment, if provided.

Explanation.—The expression 'ordinary rate of wages' means the basic time-rate wage plus allowances, if any."

[F. No. V-15013/4/72-P&D]

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1973

आदेश

का. आ. 2172.—यतः कलकत्ता पत्तन, कलकत्ता के आयुक्तों के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन, 26 डा. सुधीर बसु रोड, कलकत्ता-23 करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन करार के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — श्री के० के० रेय, अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन आयुक्त, 15 स्ट्रैण्ड रोड कलकत्ता-1

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले — श्री माखन चट्टर्जी, महा सचिव, कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन 26, डा० सुधीर बसु रोड, कलकत्ता-23

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री ए. टी. जाम्बरे, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 1, चौथी मंजिल, सिटी आईस बिल्डिंग, 298, बाजार गेट स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(1) **विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय.**—पत्तन और गोदी श्रमिकों के संबंधी केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट और उस पर तथा अन्य संबंधित मामलों पर किये गये सरकार के निर्णयों और अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक फेडरेशन द्वारा उठाई गई मांगों और उन पर किए गए और विचार-विमर्श के संदर्भ में, मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित विवादग्रस्त मामलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन माध्यस्थम् के लिए गुण दोष के आधार पर निर्णयार्थ निर्देशित किये जाने का करार किया गया है :—

(1) क्या सहायता प्राप्त औद्योगिक योजना में अर्ध-सहायता के तत्व और अनुषंगी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावित मानक मकानों के किराये की वसूली की दरों को, अर्थात् जहां मूल वेतन 200 रुपये प्रतिमाह से कम है, वहां मूल वेतन का (परन्तु नगर प्रतिकर भत्ते का नहीं) 7-1/2 प्रतिशत और जहां वह 200 रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक है, वहां मूल वेतन का (परन्तु नगर प्रतिकर भत्ते का नहीं) 10 प्रतिशत की दर से, घटाया जाना चाहिए और यदि हां, तो किसी सीमा तक ।

(2) क्या मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये संशोधित वेतनमानों में वेतन के लिए निर्धारण के मामले में मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर की गई 11-80 रुपये प्रति माह की अन्तरिम सहायता या उसके भाग को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(3) क्या मकान किराया भत्ते और प्रतिकर भत्ते के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते (अतिरिक्त महंगाई भत्ते और समय-समय पर महंगाई भत्ते में की गई वृद्धियों सहित), को अंशतः या पूर्णतः वेतन के रूप में माना जाना चाहिए ?

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिनमें अन्तर्वलित स्थापन का उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्त, 15, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता-1 से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार जिनका प्रतिनिधित्व कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन, 26-डा. सुधीर बसु रोड, कलकत्ता-23 करती है ।

(3) यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।

कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन, 26, डा. सुधीर बसु रोड, कलकत्ता-23 ।

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 41,000

विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।

41,000

यदि, मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पंचाट देने में समर्थ नहीं होता तो वह गहत के रूप में अन्तरिम सिफारिशें करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह.

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : के. के रेय,

अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन के आयुक्त ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह. माखन चट्टर्जी,

महासचिव, कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन ।

साक्षी :

(1) ह. अपाठ्य, सहायक सचिव, आल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन ।

(2) ह. अपाठ्य, उपसचिव, कलकत्ता पत्तन के आयुक्त ।

तारीख: 3 जुलाई, 1973

[संख्या एल.-39013/1/73-पी. एण्ड डी.(9)]
टी. एस. कृष्णामूर्ति. अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1973

S.O. 2172.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen as represented by Calcutta Port Shramik Union, 26, Dr. Sudhir Basu Road, Calcutta-23 ;

And, whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947.

BETWEEN

Names of Parties :

Representing employers.—Shri K. K Ray, Chairman, The Commissioners for the Port of Calcutta, 15, Strand Road, Calcutta-1.

Representing Workmen.—Shri Makhan Chatterjee, General Secretary, Calcutta Port Shramik Union, 26, Dr. Sudhir Basu Road, Calcutta-23.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri A. T. Zambre, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, 4th Floor City Ice Building, 298 Bazargate Street, Fort, Bombay.

(i) **Specific matters in dispute.**—In the context of the report of the Central Wage Board for Port and Dock Workers, the decisions of the Government thereon and other related matters, the demands raised by the All India Port and Dock Workers' Federation and the further discussions held on these, the following matters in dispute relating to Port and Dock Workers of the Major Ports are agreed to be referred to arbitration under Section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947 for decision on merits :—

(1) Whether and if so to what extent the rates for recovery of rent for standard houses proposed by Government, namely, 7-1/2 per cent of basic pay (and not City Compensatory Allowance) where basic pay is less than Rs. 200 per month and at the rate of 10 per cent of basic pay (and not City Compensatory Allowance) if it is Rs. 200 per month or more, should be reduced taking into account the subsidy element in the Subsidised Industrial Housing Scheme and other relevant factors.

(2) Whether in the matter of fixation of pay in the revised scales accepted by the Government on the basis of the Central Wage Board Report for Port and Dock Workers at Major Ports, the interim relief of Rs. 11.80 per month or part thereof granted by Government as recommended by the Wage Board should be taken into account.

(3) Whether Dearness allowance (including additional dearness allowance and increases in D.A. from time to time) in part or full should be treated as pay for the purpose of House Rent Allowance and Compensatory Allowance?

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

The employers in relation to the Commissioners for the Port of Calcutta, 15 Strand Road, Calcutta-1 and their Workmen, represented by the Calcutta Port Shramik Union, 26, Dr. Sudhir Basu Road, Calcutta-23.

(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question.

The Calcutta Port Shramik Union, 26, Dr. Sudhir Basu Road, Calcutta-23.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.

41,000

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.

41,000

If the arbitrator is not able to give his award within a period of three months from the date of his appointment, he will be free to make interim recommendations by way of relief.

Parties :

Representing employers.—K. K. Ray, Chairman, Commissioners for the Port of Calcutta.

Representing Workmen.—Makhan Chatterjee, General Secretary, Calcutta Port Shramki Union.

Witnesses :

(1) Sd/- illegible Asstt. Secy., All India Port & Dock Workers Federation.

(2) Sd/- illegible Deputy Secretary, Calcutta Port Commissioners.

Dated, the 3rd July, 1973

[No. L-39013/1/73-P&D (ix)]
T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1973

आदेश

का. आ. 2173.—यतः व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट सुन्दरनगर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों जिनका प्रतिनिधित्व व्यास सतलुज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर करता है, ने संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषय के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर, कर्मकारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस. आर. सोही होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या व्यास सतलज लिंक प्राजेक्ट, सुन्दरनगर (हि. प्र.) में नियोजित सैनिक पेन्शनर, अपनी मजदूरी के अतिरिक्त सम्पूर्ण पेंशन राशि के संदाय के लिए हकदार हैं ? यदि नहीं, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं. एल. 42012/30/73-एल. आर. 3]

New Delhi, the 19th July, 1973

ORDER

S.O. 2173.—Whereas the employers in relation to Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen represented by Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the schedule here to annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the Military pensioners employed at the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar (H.P.) are entitle to the payment of full pension amount in addition to their wages? If not, to what relief are they entitled?

[No. L. 42012/30/73/LR-III]

आदेश

का. आ. 2174.—यतः व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट सुन्दरनगर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों जिनका प्रतिनिधित्व व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर करता है, ने संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषय के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर, कर्मकारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच. आर. सोढी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या व्यास सतलुज लिंक प्राजेक्ट, सुन्दरनगर (हि. प्र.) में नियोजित और आवास सुविधा और/या निम्नस्तर आवास सुविधा में हिस्सा बंटाने के लिए अनुज्ञात कर्मचारी किसी गृह किराया भत्ते के संदाय के लिए हकदार हैं ? यदि हां तो किस तारीख से और किस वेतनमान पर ?

[सं. एल. 42012/31/73/एल. आर. 3]

ORDER

S.O. 2174.—Whereas the employers in relation to Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen represented by Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the employees employed at the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar (HP) and allowed sharing housing accommodation and or below status accommodation are entitled to the payment of any House Rent Allowance? If so, from what date and at what scales?

[No. L. 42012/31/73/LR-III]

आदेश

का. आ. 2175.—यतः व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट सुन्दरनगर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों जिनका प्रतिनिधित्व व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर करता है, ने संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषय के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर, कर्मकारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच. आर. सोढी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या व्यास सतलज लिंक प्राजेक्ट, सुन्दरनगर (हि. प्र.) में नियोजित और पंडोह, बग्गी, स्लैप्पर, बिलासपुर (गमरोला) नैला, गोलथाई, ओलिन्दा और कोटला में अस्थित कार्यप्रभारित कर्मचारी, प्रोजेक्ट पर नियोजित नियमित कर्मचारियों के लिए अनुज्ञात रियायत के सादृश्य ही एक विशेष वेतनवृद्धि के हकदार हैं ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं. एल. 42012/28/73-एल. आर. 3]

ORDER

S.O. 2175.—Whereas the employers in relation to Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen represented by Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the workcharged employees employed at the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar (H.P.) and stationed at Pandoh, Baggi, Slapper, Bilaspur (Gamrolla) Neila, Golethai, Olinda and Kotla are entitled to the grant of one special increment on the same anology on which this concession has been allowed to regular employees employed on the Project? If not, to what relief are they entitled?

[No. L. 42012/28/73/LR-III]

आदेश

का. आ. 2176.—यतः व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट सुन्दरनगर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों जिनका प्रतिनिधित्व व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर करता है, ने संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को उक्त आवेदन में उपवर्णित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में उद्धृत विषय के बारे में किसी औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करे ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त व्यास सतलज लिंक कर्मकार संघ, सुन्दरनगर, कर्मकारों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच. आर. सोढी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट, सुन्दरनगर (हि. प्र.) में नियोजित कर्मचारी कोई बीमारी छुट्टी मंजूर किए जाने के हकदार हैं? यदि हां तो किस तारीख से और कितनी ?

[सं. एल. 42012/29/73-एल. आर. 3]

करनैल सिंह, अवर सचिव

ORDER

S.O. 2176.—Whereas the employers in relation to Beas Sutlej Link Project, Sundernagar and their workmen represented by Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar, have jointly applied to the Central Government for reference of an industrial disputes that exits between them to an Industrial Tribunal in respect of the matter set forth in the said application and reproduced in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government is satisfied that the said Beas Sutlej Link Workers Union, Sundernagar represents the majority of the workmen;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute to the said Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

Whether the employees employed at the Beas Sutlej Link Project, Sundernagar (H.P.) are entitled to the grant of any sick leave? If so, from what date and to what extent?

[No. L. 42012/29/73/LR-III]

New Delhi, the 25th July, 1973

S.O. 2177.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Indian Bank Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 20th July, 1973.

BEFORE THIRU G. GOPINATH, B.A., B.L.,

PRESIDING OFFICER

INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Friday, the 13th day of July, 1973

Industrial Dispute No. 24 of 1973

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur I and a workman).

BETWEEN

Thiru P. P. Thomas, Poovanolikal House, Vakathanom P.O., Kottayam (Kerala).

AND

The Chairman, South Indian Bank Limited, Head Office, Post Box-28, Trichur-1 (Kerala).

Reference :

Order No. L. 12012/42/73/LR-III, dated 14-5-1973 of the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference and all other material papers on record and a statement having been received from the Bank that the worker has been appointed as a trainee peon and the worker being absent, this Tribunal made the following.

AWARD

This is an industrial dispute between Thiru P. P. Thomas and the South Indian Bank Limited, Trichur I in respect of the following :—

"Whether the action of the management in terminating the services of Shri P. P. Thomas, temporary peon at Kottayam branch of the Bank with effect from the 14th Augusta, 1972 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

(2) Parties were served with summons.

(3) The dispute was adjourned from 25-6-1973 to 2-7-1973 and 13-7-1973.

(4) Right from the beginning the worker Thiru P.P. Thomas was absent and on his behalf, no representation was made before me, though he was served with summons personally.

(5) A representative from the Bank appeared throughout.

(6) A statement was received from the Bank on 23-6-1973 stating that the Bank has since appointed Thiru P.P. Thomas as a trainee peon at the Attingal Branch of the Bank and that he joined duty on 14-5-1973. With the statement is enclosed a letter dated 2-4-1973 by the worker to the Conciliation Officer withdrawing his petition dated 17-8-1972 filed before the Conciliation Officer. This letter was probably sent to the Conciliation Officer ofter the conciliation report was sent to the Government.

(7) Even if the worker found it difficult to come from Kottayam to appear before this Tribunal at Madras, he might have sent his claim statement through post if he had any claim to prefer. No claim statement was received from the worker till this day.

(8) From the statement received from the management, it is seen that Thiru P.P. Thomas has been appointed as a trainee peon and that he is at present working in the Bank. Therefore the worker has apparently no interest in this dispute.

(9) In the circumstances, I pass an award negativing the demand of the worker since he has been appointed by the Bank as a trainee peon.

Dated this 13th day of July, 1973.

G. GOPINATH, Industrial Tribunal

[No. L-12012/42/73-LR. III]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973